



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 2018/ ज्येष्ठ 21, 1940

No. 205]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 11, 2018/ JYAISTHA 21, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2018

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ग्राइडिंग मीडिया बाल्स' (फोर्ज्ड ग्राइडिंग मीडिया को छोड़कर) से आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

मामले की पृष्ठभूमि

- फा. सं. 7/7/2017- डी जी ए डी.—1.** सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 जिसे 1995 में संशोधित किया गया था और सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) ने चीन जन. गण. और थाईलैंड (इसके पश्चात संबद्ध देशों के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'ग्राइडिंग मीडिया बाल्स' (फोर्ज्ड ग्राइडिंग मीडिया को छोड़कर) (इसके पश्चात संबद्ध वस्तुओं के रूप में संदर्भित) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की। प्राधिकारी ने दिनांक 22 मई, 2012 के अपनी अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/34/2010- डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। इन शुल्कों को केन्द्रसरकार द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2012 के सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 36/2012-सीमाशुल्क (पाटनरोधी शुल्क) के माध्यम से लगाया गया था।
2. जबकि, इस नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1995 की धारा 9 क(5) के संबंध में, उक्त अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये पाटनरोधी शुल्क, यदि इसे पूर्व में समाप्त नहीं किया गया हो, इस शुल्क के समाप्त होने के पूर्व यदि किसी समीक्षा में आरंभ नहीं किया गया हो, इस प्रकार के लगाये जाने की स्थिति से पांच वर्षों के समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा, निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि इन शुल्कों समाप्त न किये जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी

रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस उपाय के समाप्त होने की तिथि से पूर्व एक उचित समय अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किये गये विधिवत सिद्ध किये हुए अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करे कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है।

3. और जबकि, उपरोक्त नाम के क्षेत्रों/ प्रक्षेत्रों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये उपर्युक्त सामानों के पाटन के जारी रहने अथवा इसके फिर से उत्पन्न होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए और चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ करने के लिए अनुरोध करते हुए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स अर्थात् मैसर्स ए आई ए इंजीनियरिंग लिमि. तथा मैसर्स वेलकास्ट स्टील्स लिमि. के प्रमुख घरेलू उत्पादक द्वारा एक याचिका दायर की गई है।
4. घरेलू उद्योग की ओर से दायर किये गये पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत सिद्ध किए गए आवेदन को देखते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध सामानों के संबंध में इन शुल्कों को सतत् रूप से लगाये जाने के लिए आवश्यकता की समीक्षा करने और इस तथ्य की जांच करने की क्या इस प्रकार के शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है, के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा का 9 क(5) के अनुसार एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 जुलाई, 2017 से एक अधिसूचना संख्या 7/7/2017 – डी जी ए डी जारी की। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 34/2017 – सीमा शुल्क (पाटनरोधी शुल्क) के द्वारा 15 जुलाई, 2018 तक बढ़ाया गया था।
5. वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र में चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए उपर्युक्त सामानों के आयातों के संबंध में मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. सामान्य प्रक्रिया

6. इस प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच को आरंभ करने की अधिसूचना जारी करते हुए आम सूचना के जारी किये जाने के बाद इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :
 - i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावास/ प्रतिनिधियों को अधिसूचित किया है।
 - ii. प्राधिकारी ने इन आवेदनों द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावास, संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को जांच आरंभ करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे जांच आरंभ करने संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराये।
 - iii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को इस आवेदन का अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
 - iv. भारत में संबद्ध देशों के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे चीन और थाईलैंड के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रश्नावली का जवाब देने की सलाह दें। इन उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति चीन जन. गण. और थाईलैंड के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ साथ उन्हें भी भेजा गया था।
 - v. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी :
 - क. मैसर्स मेगोटेअक्स कं. लिमि., थाईलैंड
 - ख. मैसर्स मेगोटेअक्स एलॉयड मेटेरियल (सूज़ोउ) कं. लिमि., चीन
 - vi. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर केवल मैसर्स मेगोटेअक्स कं. लिमि., थाईलैंड ने दिया।

vii. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी :

क.	ए सी सी लिमिटेड
ख.	सेंचुरी सीमेंट
ग.	ग्रासिम इंडस्ट्री
घ.	चारिओट स्टील एंड पावर (प्रा.) लिमि.
ङ.	एलकॉन सीमेंट कंपनी
च.	चाउगुले एंड कं.
छ.	अम्बूजा सीमेंट कं.
ज.	चुनार चुरक सीमेंट लिमि.
झ.	आंध्रा सीमेंट कं. लिमि.
ञ.	सीमेंट मेनिफेक्चरिंग कं. लिमि.
ट.	दुर्गा सीमेंट वर्क्स
ठ.	श्री दिग्विजय सीमेंट
ड.	अजंजी पार्टलैंड सीमेंट लिमि.
ढ.	डेकन सीमेंट लिमि. (002)
ण.	एशियन सीमेंट एंड कांक्रिट
त.	डायमण्ड सीमेंट्स
थ.	भारत हैवी इलेक्ट्रीकलस लिमि.
द.	इको सीमेंट इण्डिया लिमि.
ध.	बिनानी सीमेंट लिमि.
न.	ग्रीन वैली इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.
प.	बिरला कारपोरेशन लिमि.
फ.	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन
ब.	गुजरात सिद्धी सीमेंट लिमि.
भ.	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन
म.	हिनडेलको इस्ट्रीज लिमि. (दाहेज)
य.	हम्बोल्ट वेडेज इण्डिया प्रा. लिमि. (सीमेंट डिवीजन)
र.	हिन्दुस्तान जिक लिमि.
ल.	इण्डिया रिसोर्स लिमि.
व.	द इण्डिया सीमेंट लिमि.
श.	जे. के. सीमेंट वर्क्स
ष.	जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमि.
स.	जिंदल स्टील पावर लिमि.
ह.	जे पी रेवा प्लांट
क्ष.	जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लिमि.
त्र.	जे. के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स

ज.	जयप्रकाश एसोसिएट लिमि. चुनार
कक.	ककटिया सीमेंट सुगर एंड इंडस्ट्रीज
खख.	किरथी इंडस्ट्रीज लिमि. - मेलाक
गग.	खेबर इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमि. - काश्मीर
घघ.	केसोरम सीमेंट - बसंतनगर
ङङ.	लाफारगे इंडिया प्रा. लिमि. - अरसमेटा
चच.	मद्रास सीमेंट लिमि. - जयथिपुरम
छछ.	मेहर सीमेंट
जज.	माही सीमेंट (इंडो जिंक लिमिटेड का एक प्रभाग)
झझ.	मनिकगढ़ सीमेंट (सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंड. लिमि. का एक प्रभाग)
ञञ.	मनदोबी पेलेट्स (चाउगुले एंड कम्पनी लिमि. का एक प्रभाग)
टट.	मेघालय सीमेंट लिमिटेड
ठठ.	मेघा टेक्निकल एंड इंजीनियर्स प्रा. लिमि.
डड.	एम एस पी स्टील एंड पावर लिमि. (पेलेट प्लांट)
ढढ.	मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड
णण.	महाराष्ट्रा स्टेट पावर जेनरेशन
तत.	माई होम सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमि. - मेला
थथ.	ओसल इण्डिया लिमिटेड - राजगंगपुर
दद.	हेडल्वेग सीमेंट इण्डिया लिमि.
धध.	ओरियंट सीमेंट - देवापुर
नन.	एन सी एल इंडस्ट्रीज लिमिटेड - मेट्टापल्ली
पप.	एन जी एस व्हाईट सीमेंट कंपनी
फफ.	पनयाल सीमेंट्स एंड मिनिरल इंडस्ट्रीज
बब.	पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमि.
भभ.	पाराशक्ति सीमेंट इंडस्ट्री लिमि.
मम.	सागर सीमेंट लिमिटेड - मेट्टापल्ली
यय.	परिसम सीमेंट लिमिटेड
रर.	सौराष्ट्रा सीमेंट लिमि.
लल.	रेन कोमोडिटाइज लिमि. - कुरनूल
वव.	शिवा सीमेंट लिमि.
शश.	रश्मी सीमेंट लिमि. (सीमेंट डिवीजन)
षष.	श्री सीमेंट लिमि. - आर ए एस (एस सी आर)
सस.	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि.
हह.	त्रिनयनी सीमेंट (प्रा.) लिमि.

क्षक्ष.	श्रीराम सीमेंट वर्क्स (डी सी एम श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमि. का एक प्रभाग)
त्रत्र.	ट्रम्बू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमि.
जज.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि. – ए. पी.
ककक.	टाटा केमिकल्स लिमि. – मीठापुर
खखख.	यू. पी. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि.
गगग.	जुअरी सीमेंट लिमि. – येरागुन्टला
घघघ.	वसावदत्ता सीमेंट – सेडम
ङङङ.	पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमि.
चचच.	परिसम सीमेंट लिमि. – यूनिट – आईआई
छछछ.	सरदा एनर्जी एंड मिनिरलस लिमि.
जजज.	सुडे मिनिरल्स एंड केमिकल्स (प्रा.) लिमि.
झझझ.	सालोनी इंडस्ट्रीज
ञञञ.	समरुथि सीमेंट लिमि.

viii. इस प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रश्नावली के उत्तर में, केवल निम्नलिखित कंपनी ने आयातक की प्रश्नावली के उत्तर का जवाब दिया :

क. बिरला शक्ति सीमेंट

ix. इसके अलावा, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकार ने जांच के आरंभ किये जाने का उत्तर प्रस्तुत किया था :

क. माई होम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. – महा सीमेंट

- x. प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच के लिए खुली रखी गई एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- xi. पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों का लेन देन वार ब्यौरा जिसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था, उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने इन लेन देन की उचित जांच करने के बाद आयातों की मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xii. सामान्य रूप से स्वीकार किये लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन की आदर्शतम लागत और उसे बनाने एवं बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) तय की गई है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiii. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए इन हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के वास्ते 16 मार्च, 2018 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की, जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, उत्तर देने वाले निर्यातक, आयातकों और आयातक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। उन प्रतिनिधियों जिन्होंने मौखिक सुनवाई के समय अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत किए थे, को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोधों के रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। इन हितबद्ध पक्षकारों को विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों का प्रत्युत्तर अनुरोध के रूप में देने के लिए अवसर दिया गया था।
- xiv. घरेलू उद्योग के आंकड़ों का तालिका सत्यापन और निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर को उस सीमा तक सत्यापन किया गया था, जिस सीमा तक इसे आवश्यक समझा गया। जहां भी लागू हुआ आवश्यक संशोधन के साथ केवल इस प्रकार की संशोधित सूचना पर इस जांच परिणाम के उद्देश्य से विश्वास किया गया है।

- xv. वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि अप्रैल 2016-17 जांच की अवधि के रूप में है। हालांकि क्षति की जांच की अवधि पर 2013-14, 2014-15, 2015-16 की अवधि और जांच की अवधि के रूप में विचार किया गया है।
- xvi. प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हैं, दोनों के लिए 06 जून, 2018 तक का समय देते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण 30 मई, 2018 को जारी किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- xvii. जहां भी संगत पाया गया इस जांच की अवधि के दौरान इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का समाधान इस प्राधिकारी द्वारा इस दस्तावेज में किया गया है।
- xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, इस प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे जहां भी आवश्यक हुआ को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना पर गोपनीय के रूप में माना गया है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।
- xix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना दिए जाने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से नहीं दिया है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और इस जांच परिणाम को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड किया है।
- xx. इस दस्तावेज में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार की गई सूचना का द्योतक है।
- xxi. प्राधिकारी द्वारा विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 67.95 रुपये के रूप में लिया गया है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

7. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद वही है, जो मूल जांच में था। इसकी परिभाषा "विचाराधीन उत्पाद 'ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स (फोर्ड ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स को छोड़कर)' है, के रूप में दी जा सकती है। ('ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स' संक्षेप में 'जी एम बाल्स') का उत्पादन विविध उपयोगों में प्रयोग के लिए अलग अलग आकारों, बनावटों और संरचनाओं में किया जाता है। इसके अलावा, यह ग्राहकों की अलग अलग आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग कठोरता में उपलब्ध है।"
- ii. 'ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स' विविध उपयोगों में प्रयोग के लिए अलग अलग आकारों, बनावटों और संरचनाओं में उपलब्ध है। वे ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार अलग अलग कठोरता में उपलब्ध है। ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स का उपयोग भारी और कड़ी सामग्रियों को क्रेस करने और पीसने के लिए बाल मिल में किया जाता है।
- iii. (ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स कास्टिंग बाल्स रूप में भी ज्ञात) का व्यापक रूप से उपयोग सीमेंट संयंत्रों में चूने का पत्थर और किलिंगकर, खानों में खनिज अयस्क और तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले को तोड़ने और उसे पीसने के लिए ग्राइंडिंग मिलों में किया जाता है।
- iv. ग्राइंडिंग मीडिया को उच्च क्रॉम मेटोलार्जी में ढाला जाता है जो इसे रुकावट/ टूटने के खतरे के बिना अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय काल प्रदान करता है। उच्च क्रॉम कास्ट बाल्स का समरूप वियर प्रोफाइल होता है जो ग्राइंडिंग मिलों, जिनमें उनका उपयोग किया जाता है, के लिए लगातार उत्पादन सुनिश्चित करता है।
- v. ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स का उत्पादन अलग अलग आकारों में किया जाता है जो 12 एम एम से शुरू होकर 110 एम एम तक होता है। इसका उत्पादन भी अलग अलग क्रोम संघटक जैसे जी12, जी14, जी15, जी18, जी21, जी22 आदि के रूप में किया जाता है। जी12 में 'जी' का आशय ग्राइंडिंग मीडिया से होता है और '12' क्रॉम की संघटक की मात्रा को

दर्शाता है। अलग अलग आकार के बाल्स का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है। उदाहरण के लिए जी 12 का उपयोग 50 से 90 एम एम के बाल आकार के साथ सीमेंट को पीसने में किया जाता है।

- vi. आयात किये गये उत्पाद और घरेलू उत्पाद तथा सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के लिए उचित तुलना के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता अलग अलग उत्पाद प्रकारों में भिन्नता का सुझाव देते हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने इस सूचना को उत्पाद के प्रकारों पर अलग अलग किया है।
- vii. विचाराधीन उत्पाद का व्यापक रूप से उपयोग सीमेंट निर्मित सामग्रियों, धातु खदान, कोयले के कीचड़, तापीय विद्युत संयंत्र, रासायनिक इंजीनियरिंग, किरेमिक उद्योग, ढोप उद्योग, हल्के उद्योग जैसे कागज निर्माण और चुंबकीय सामग्री आदि में चूरन बनाने हेतु किया जाता है। संबद्ध सामानों का वर्गीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 73 के सीमा शुल्क उप शीर्षक 7325 9100 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह इस जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
- viii. उपयोग की गई प्रौद्योगिकी और घरेलू तथा आयात किये गये उत्पाद की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है और इनका उपयोग तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। उपभोग का इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में जिस पर भरोसा किया गया है, विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जांच की है।
- ix. संबद्ध ग्राइंडिंग मीडिया फोर्ड में से प्रत्येक बाल्स जिसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है, लक्षणों जैसे भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन एवं अलग अलग संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स में से प्रत्येक के साथ इन सामानों का शुल्क वर्गीकरण के संबंध में अलग अलग रूप में तुलनीय हैं।
- x. वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच जिस पर विश्वास किया गया है, में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जांच की है।

ग. 2 हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

8. किसी भी उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वे उत्पाद जिन पर शुल्क लागू हैं 'ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स' (फोर्ड ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स को छोड़कर) है। इस समीक्षा में समग्र उत्पाद शामिल हैं और इसके पश्चात उनका संदर्भ संबद्ध वस्तुओं के रूप में लिया गया है।
10. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस प्राधिकारी द्वारा पूर्व में की गई सिफारिश के अनुसार पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर लागू है, अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वर्तमान जांच में वही रहता है जो मूल और बाद की समीक्षा जांचों में है। पूर्व की जांचों में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद नीचे दिए गए अनुसार है।
 - 'ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स (संक्षेप में 'जी एम बाल्स') का उत्पादन विविध उपयोगों में प्रयोग के लिए अलग अलग आकारों, बनावटों और संरचनाओं में किया जाता है। इसके अलावा, यह ग्राहकों की अलग अलग आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग कठोरता में उपलब्ध है।'
 - विचाराधीन उत्पाद का व्यापक रूप से उपयोग सीमेंट निर्मित सामग्रियों, धातु खदान, कोयले के कीचड़, तापीय विद्युत संयंत्र, रासायनिक इंजीनियरिंग, किरेमिक उद्योग, ढोप उद्योग, हल्के उद्योग जैसे कागज निर्माण और चुंबकीय सामग्री आदि में चूरन बनाने हेतु किया जाता है। संबद्ध सामानों का वर्गीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 73 के सीमा शुल्क उप शीर्षक 7325 9100 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह इस जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
11. रिकार्ड पर सूचना के संबंध में विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद की

तुलना विचाराधीन उत्पाद से उन लक्षणों जैसे भौतिक और रासायनिक लक्षणों, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन तथा इन सामानों का शुल्क वर्गीकरण के संबंध में किया जा सकता है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं। ग्राहक इन दोनों का उपयोग एक दूसरे उत्पाद के स्थान पर कर रहे हैं।

12. इस प्रकार से प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र एवं स्थान

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

13. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र एवं स्थान के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- वर्तमान याचिका ए आई ए इंजीनियरिंग लिमि. और वेलकास्ट स्टील लिमि. जो संबद्ध वस्तुओं का भारत में उत्पादन करता है, द्वारा थाईलैंड और चीन जन. गण. के मूल के ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की समीक्षा और उसे जारी रखने के लिए दायर की जा रही है।
- केवल याचिकाकर्ता का ही भारतीय उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें न तो संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही यह संबद्ध देशों में संबद्ध उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित है।
- अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन के संबंध में कोई प्रकाशित सूचना उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता ने अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन का निर्धारण उनके कच्चे माल के आयातों, घरेलू बिक्री, अलग अलग कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों और आयातों के आधार पर किया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

14. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और स्थान के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- किसी भी उत्पादक/ निर्यातक/ आयातक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) को नीचे दिए गए अनुसार घरेलू उद्योग को परिभाषित किया गया है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

16. यह आवेदन ए आई ए इंजीनियरिंग लिमि. और वेलकास्ट स्टील लिमि. द्वारा दायर किया गया है। भारतीय उत्पादन का विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :

क्र. सं.	विभाग का नाम	यूओएम	विवरण			
			2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
1	याचिकाकर्ता कंपनी					
क	ए आई ए इंजीनियरिंग लिमि.	मी. ट.	***	***	***	***
ख	वेलकास्ट स्टील्स लिमि.	मी. ट.	***	***	***	***
ग	कुल याचिकाकर्ता कंपनियां	मी. ट.	***	***	***	***
2	अन्य भारतीय उत्पादक	मी. ट.	***	***	***	***
क	कुल भारतीय उत्पादन	मी. ट.	1,66,618	1,90,021	1,74,349	2,13,292
क्र. सं.	विभाग का नाम	यूओएम	शेयर (%)			

			2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
1	याचिकाकर्ता कंपनी					
क	याचिकाकर्ता कंपनी	%	61%	69%	73%	70%
ख	ए आई ए इंजीनियरिंग लिमि.	%	23%	17%	12%	17%
ग	वेलकास्ट स्टील्स लिमि.	%	84%	86%	85%	88%
2	अन्य भारतीय उत्पादक कुल याचिकाकर्ता कंपनियां	%	16%	14%	15%	12%
क	कुल याचिकाकर्ता कंपनियां	%	100%	100%	100%	100%

17. प्राधिकारी रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट करते हैं कि कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा 88 प्रतिशत है और कुल भारतीय उत्पादन का यह बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और यह नियम 2(ख) के अनुसार भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता अथवा अलग अलग संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है।
18. उपर्युक्त को ध्यान में रखकर तथा उचित जांच के पश्चात, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक संबद्ध सामानों के लिए स्थायी आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

गोपनीयता

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

19. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
- उत्तर देने वाले निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर से संबंधित फाइल में अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है। मैसर्स मेगोटेअक्स क. लिमि. द्वारा दायर की गई निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर को उनके द्वारा दावा किए गए अत्यधिक गोपनीयता के कारण अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। निर्यातक ने इस सूचना, जिसे निर्यातक को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना अपेक्षित है, के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।
 - निर्यातक ने गोपनीयता के प्रावधानों का दुरुपयोग किया है, जिनसे घरेलू उद्योग के उनके हित का बचाव करने के लिए अधिकार में कटौती की है और इस प्रकार के दावे को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
 - बहुत मौलिक सूचना उत्पाद का नाम, ग्रेड, वेबसाइट से संबंधित सूचना, वितरण का माध्यम, इसके कार्यालयों का ब्यौरा अन्य बातों के साथ साथ गोपनीय रखी गयी है। कोई उचित अगोपनीय तार इन निर्यातकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
 - निर्यातक ने उत्पादन में शामिल कारखानों तथा उत्पादन किए गए उत्पाद, दस्तावेजों का नाम के संबंध में कोई सूचना, भारत में निर्यात के संबंध में सूचना, कंपनी के सामानों की बिक्री, बिक्री कीमत की संरचना, संस्थापित क्षमता दर्शाने वाला विवरण, उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना, सहायक कंपनी आदि से संबंधित सूचना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।
 - निर्यातक से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताओं, भारत के अलावा वैकल्पिक बाजारों की उपलब्धता, निर्यातक के पास जांच के अधीन वस्तु का भंडार, इन कीमतों जिन पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात तीसरे देशों में किया जा रहा है और इस उत्पाद के लिए स्थानीय मांग के संबंध में सूचना दे तथा उन कीमतों का पता लगायें जिन पर संबद्ध निर्यातकों द्वारा इस उत्पाद का निर्यात किए जाने की संभावना है और किस प्रकार से इसकी तुलना घरेलू उद्योग की कीमतों और क्षति रहित कीमत से की जा सकती है। वर्तमान मामले में, निर्यातक ने उपर्युक्त के लिए सभी सूचनाओं के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।
 - निर्यातक ने उनके द्वारा दायर की गई सूचना का कोई अगोपनीय सार उपलब्ध नहीं कराया है और इससे घरेलू उद्योग के अपने हित की रक्षा करने के अधिकार में बहुत अधिक कटौती हुई है और निर्यातक ने गोपनीयता के प्रावधानों का

दुरुपयोग किया है। इस प्रकार के दावों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और निर्यातकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे किस प्रकार की सूचना को प्रकट करें अथवा सूचना के अगोपनीय सार को पर्याप्त रूप में उपलब्ध करायें।

- vii. उस स्थिति में भी जब किसी पक्षकार ने इस जांच में भाग लिया हो, परंतु प्राधिकारी द्वारा मांगी गई उपलब्ध सूचना को उपलब्ध नहीं कराया हो, तब पक्षकार को इस प्राधिकारी द्वारा सहयोगी के रूप में माना जा सकता है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. मैसर्स मेगोटेअक्स ने इसी सूचना के गोपनीयता की मांग की है जिसे स्वयं शिकायतकर्ता ने गोपनीयता की मांग की है।
- ii. मैसर्स मेगोटेअक्स ने केवल उसी सूचना की गोपनीयता की मांग की है जो व्यापार संवेदनशील है और जिसे प्रतियोगी को प्रकट करने से मेगोटेअक्स के व्यापार हित को गंभीर नुकसान हो सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

21. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है :

“गोपनीय सूचना”

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच की गई है और उसका समाधान तदनुसार किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, इस प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे जहां भी आवश्यक हुआ को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना पर गोपनीय के रूप में माना गया है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई सूचना जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है, को गोपनीय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

विविध

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

23. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

- i. ब्राजील के प्राधिकारी ने इसी उत्पाद के लिए भारत के विरुद्ध पाटनरोधी तथा सब्सिडीरोधी जांच शुरू की है। लगाया गया पाटनरोधी शुल्क 12.2 प्रतिशत है और सी वी डी जांच चल रही है।
- ii. उसे भारतीय निर्यातों को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। पाटनरोधी शुल्क निर्यात कीमत के लागत की तुलना में बहुत अधिक होने के बावजूद भारतीय उत्पादों पर लगाया गया है।

- iii. निर्यातक ने पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए अध्याय 73 के बजाय अध्याय 84 के अंतर्गत इन सामानों का निर्यात किया है। पाटनरोधी शुल्क से बचने के प्रयास को गलत एच एस कोड के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का 186 मी. ट. का निर्यात करते हुए निर्यातक की प्रथा से देखा जा सकता है।
- iv. घरेलू उद्योग ने लेन देन वार आयात आंकड़े पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं जो यह दर्शाता है कि कुल 186 टन आयात अध्याय 84 के अंतर्गत आयात किया गया है और उसके साथ साथ यह सिद्ध करने के लिए संगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि विचाराधीन उत्पाद का आयात गलत वर्गीकरण के तहत किया गया है।
- v. यह देखा जायेगा कि पिछले दो वर्षों से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में बहुत अधिक गिरावट आई है और विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों के निर्यातकों ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से इन कीमतों में बदलाव किया है और निर्णायक समीक्षा जांच को प्रभावित करने के लिए अपने निर्यात की मात्राओं में भी बदलाव किया है।
- vi. इन निर्यातकों द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच को प्रभावित करने तथा पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने की मांग करने के उद्देश्य से एक सोची समझी कार्यवाही की गई थी।
- vii. मूल कंपनियों से सहयोग के अलावा, थाईलैंड की सरकार भी भारत से आयातों पर अत्यधिक सीमा शुल्क लगाकर इस कंपनी को सुरक्षा देती है। इस बीच, भारत सरकार थाई उत्पादकों को सीमा शुल्क में रियायत दी है।
- viii. भारत और थाईलैंड द्वारा एफ टी ए अन्य देशों की तुलना में थाईलैंड ने उत्पादकों/ निर्यातकों को विशेष रियायतें प्रदान करती हैं। जबकि, भारत सरकार ने विचाराधीन उत्पाद के लिए थाईलैंड को शुल्क रियायत दी, थाई सरकार ने भारतीय निर्यातकों को इसके बदले रियायतें नहीं दीं।
- ix. आसियान करार के पीछे का उद्देश्य इन देशों के बीच मुख्य व्यापार को प्रोत्साहित करना और व्यापार अवरोधों को दूर करना था तथा इसके साथ ही निर्यात करने वाले देशों को एक उचित प्रतियोगी बाजार उपलब्ध कराना था। निर्यातकों ने आसियान करार के अंतर्गत उन्हें दिए जाने वाले लाभ का अनुचित लाभ उठाया है।
- x. शून्य शुल्क के बजाय विचाराधीन उत्पाद के लिए 10 प्रतिशत सीमा शुल्क पर विचार करने के संबंध में, हल्दोर टोपसे का माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है और उस पर विश्वास किया जा सकता है, जहां माननीय न्यायालय ने दो अलग अलग सीमा-शुल्कों के कारण उसी उत्पाद के लिए दो अलग अलग पाटन और क्षति मार्जिन की गणना की पुष्टि की है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

- i. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत समीक्षा के कार्यक्षेत्र पर प्रश्न उठाया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस तथ्य को देखने के लिए कि घरेलू उद्योग इन कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अधिक सीमा तक बढ़ाकर पोषण कर रहा है, शुल्क को लगाने, निर्यात करने वाले देशों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में परिवर्तन के समय से आयात करने वाले देशों में पाटित उत्पाद के उत्पादन, मांग और आवश्यकता के पैटर्न में परिवर्तन जैसे कतिपय कारकों की जांच करे।
- ii. प्राधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत उल्लिखित कारकों का समाधान करें अन्यथा शुल्क के निर्धारण का औचित्य नहीं ठहराया जायेगा।
- iii. आसियान करार के अंतर्गत सीमा शुल्क के जो दर प्राप्त हो रही है उसी के अनुसार सीमा-शुल्क के वरियतम दर के बजाय थाईलैंड से जी एम बाल्स के पहुंच मूल्य की गणना करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी को 10 प्रतिशत का मूल सीमा-शुल्क देना चाहिए।
- iv. आसियान करार में उत्पाद दर उत्पाद आयात शुल्क की परस्पर कटौती पर विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार की परस्परता राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार यह तर्क कि थाईलैंड ने भारत से जी एम बाल्स पर आयात शुल्क का वरियतम दर उपलब्ध नहीं कराया है, पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

- v. घरेलू उद्योग को पाटनरोधी उपायों के अंतर्गत अत्यधिक सुरक्षा नहीं दी गई है। जिसके फलस्वरूप प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है।
- vi. शिकायतकर्ता 'वास्तविक रूप में एकाधिकार का लाभ उठा' रही है।
- vii. घरेलू उद्योग इस स्थिति का लाभ इन कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अधिक सीमा तक बढ़ाकर उठा रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 25. इस अनुरोध के संबंध में कि सीमा-शुल्क पर विचार 0 प्रतिशत की तुलना में 10 प्रतिशत के रूप में किया जाना चाहिए क्योंकि निर्यातक आसियान करार के अंतर्गत इसका लाभ उठाते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस संबंध में कानून बिलकुल सशक्त है कि सीमा-शुल्क दर वही लिया जायेगा जो लागू है।
- 26. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कानून में स्पष्ट रूप से यह विचार किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को समय समय पर आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसा पाया गया है कि घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की संभावना है। पाटनरोधी कानून अनुचित व्यापार तथा समाप्त करने के लिए है और घरेलू उद्योग को इस समान अवसर प्रदान करने के लिए है। प्राधिकारी इन कानूनों के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करने के बाद ही पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।
- 27. घरेलू उद्योग के एकाधिकारवादी व्यवहार के मुद्दे पर, यह नोट किया जाता है कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य इस पाटन को समाप्त करना है जो हो रहा है अथवा जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने (एस एस आर के मामले में) की संभावना है तथा भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतियोगिता की स्थिति फिर से स्थापित करना है, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी नियमावली से, यह आशय नहीं निकाला जा सकता है कि किसी कंपनी यदि वह एकाधिकारवादी भी हो, को अनुचित आयातों के विरुद्ध प्राधिकारी की कार्यवाहियों का अनुरोध करने से रोका जा सकता है।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

- 28. सीमा-शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में 'सामान्य मूल्य' का आशय निम्नलिखित से है :

"व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की विक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम विक्री मात्रा के कारण ऐसी विक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, विक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

- 29. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित अनुरोध किया :

- i. चीन को इस कारण गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाने की आवश्यकता है कि चीन में लागतें और कीमतें बाजार शक्तियों को उचित रूप से प्रदर्शित नहीं करती हैं। अनुबंध-1 के पैरा 8 में उन मानदण्डों विशेष रूप से उल्लेख है, जिस पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिए जाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इसका आशय यह भी है कि यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तब चीन की लागतों और कीमतों को अपनाया जा सकता है।

- ii. चीन के उत्पादकों से यह अपेक्षित है कि वे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण के अंतर्गत कार्यरत कंपनियों के रूप में माना जाना चाहिए और प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्यवाही कर सकते हैं।
- iii. थाईलैंड के केवल ज्ञात आयातकों को अभी तक सीमा-शुल्क के आंकड़ों में नहीं सूचित किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इन खेपों को मार्च 2017 में स्वीकृत किया गया है। हालांकि, याचिकाकर्त्ताओं को उस मात्रा और कीमत जिस पर थाई के निर्यातक ने प्रस्तावित जांच की अवधि में ऑर्डर लिया है, की पूरी जानकारी है और उन्होंने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से उसे अपनाया है।

अन्य हितवद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

30. अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- i. शुल्क को रद्द किए जाने के बाद आयातों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, परंतु यह दर्शाने के लिए कोई मानदण्ड नहीं है कि शिकायतकर्त्ता को कोई नुकसान होगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

चीन में सामान्य मूल्य

31. चीन के एक्सेशन प्रोटोकाल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है :

“गेट 1994 के अनुच्छेद VI, शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन के संबंध में करार (“पाटनरोधी करार”) और एस सी एम करार उन कार्यवाहियों में लागू होगा जिनमें निम्नलिखित के अनुरूप इस व्यापार संगठन के एक सदस्य को चीन के मूल के आयात शामिल हों :

(क) गेट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत की तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य या तो चीन की कीमतों अथवा जांच के अंतर्गत उद्योग के लिए कीमतों अथवा एक पद्धति जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में लागतों अथवा घरेलू कीमतों से कड़ी तुलना के आधार पर न हो, का उपयोग करेंगे।

(i) यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में तमाम उत्पाद का उत्पादन करने वाला उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं तब आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कीमत की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांच के अधीन उपयोग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे;

(ii) आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य एक पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जो चीन में लागतों अथवा घरेलू कीमतों से कड़ी तुलना के आधार पर न हो, यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा नहीं सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।

(ख) एस सी एम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में उल्लेख की गई सविस्ती का समाधान करते समय, एस सी एम करार के संगत प्रावधान लागू होंगे; हालांकि, यदि उस उपयोग में विशेष दिक्कतें सामने आती हों, तब आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य सविस्ती लाभ की पहचान और उसका माप करने के लिए इन पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना पर विचार किया जा सकता है कि चीन में मौजूदा शर्तें और स्थितियां उपयुक्त बैंच मार्क के रूप में हमेशा उपलब्ध नहीं रह सकती है। इस प्रकार की पद्धतियों को लागू करने में जहां भी संभव हो आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य को चीन के बाहर मौजूद शर्तों और स्थितियों के उपयोग पर विचार करने के पूर्व इस प्रकार की मौजूदा शर्तों और स्थितियों का समायोजन करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य पाटनरोधी प्रथाओं से संबंधित समिति के उप-अनुच्छेद (क) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों को अधिसूचित करेंगे और सविस्ती एवं प्रतिकर उपायों से संबंधित समिति के उप-अनुच्छेद (ख) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों को अधिसूचित करेंगे।

चीन द्वारा आयात करने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य की राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह सिद्ध किए जाने के बाद की यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, उप अनुच्छेद (क) के प्रावधानों का समाप्त कर दिया जायेगा बशर्ते की आयात करने वाले सदस्य का राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन में किसी को बाजार अर्थव्यवस्था मानदण्ड निहित हो। किसी भी घटना में उप अनुच्छेद (क) (iii) के प्रावधान एक्सेशन की तिथि के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जायेगा। इसके अलावा, अगर चीन आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य की राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यह सिद्ध करता है कि किसी खास उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तब उप अनुच्छेद (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।”

32. अनुच्छेद 15 का यह अर्थ होता है कि उप अनुच्छेद के एक के प्रावधान चीन के एक्सेशन की तिथि से 15 वर्षों में समाप्त हो जायेगी। इस अनुच्छेद के प्रावधान 11 दिसंबर, 2017 को समाप्त हो गए थे। चूंकि, घरेलू उद्योग को क्षति उत्पन्न करने वाले पाटन का तथ्य जांच की अवधि के आधार पर सिद्ध हो गई है, अतः केवल जांच की अवधि के दौरान मौजूद स्थितियां वर्तमान जांच के प्रयोजन से संगत, उपर्युक्त और आवश्यक हैं। वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) अप्रैल 2016-17 है क्योंकि अनुच्छेद 15 का उप अनुच्छेद जांच की अवधि के दौरान मौजूद नहीं था। अतः प्राधिकारी उस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जो चीन में लागतों अथवा घरेलू कीमतों के साथ कड़ी तुलना के आधार पर नहीं हो। यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से इस तथ्य को नहीं दर्शा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।
33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में चीन जन. गण. को भारत और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों के रूप में माना गया है। चीन जन. गण. को इस नियमावली के संबंध में निर्यात करने वाले देश अथवा अलग अलग निर्यातकों द्वारा इस पूर्वानुमान के खंडन के अधीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है।
34. किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए तथा चीन की किसी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान के खंडन न किए जाने की स्थिति में प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मानने के लिए इसे उपयुक्त समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार आगे की कार्यवाही करने का प्रस्ताव करते हैं।

चीन जन. गण. के सभी उत्पादक/ निर्यातक

35. चूंकि चीन जन. गण. के किसी उत्पादक ने इस जांच में सहयोग नहीं किया है और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(2) के अनुसार गैर बाजार दर्जे का खंडन करने के लिए कोई सूचना नहीं दी है। इस कारण से पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(2) के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान का खंडन नहीं किया गया है। इस कारण से प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकार्ड पर पर्याप्त सूचना के नहीं दिए जाने पर जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने इस पद्धति 'कोई अन्य उचित आधार' अपनाकर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
36. इस कारण से प्राधिकारी ने रिकार्ड पर उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विचार करने के उद्देश्य से चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य तय किया है।

थाईलैंड के निर्यातक/ उत्पादक, मैसर्स मेगोटेक्स कं. लिमि. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

37. सर्वप्रथम यह देखा गया था कि क्या उत्तर देने वाले निर्यातक/ उत्पादक द्वारा उनके घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री उनकी घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देने के लिए सांकेतिक अथवा व्यवहार्य की और यह कि क्या व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि उत्तर देने वाले द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार पूरी कर ली गई थी। उत्तर देने वालों ने अपने घरेलू बाजारों में समान वस्तु की बिक्री का लेन देन वार ब्यौरा उपलब्ध कराया है। इस प्रकार से उपलब्ध कराई गई सूचना पर व्यापार जांच और पर्याप्तता परीक्षण की सामान्य अवधि पूरी कर लिये जाने के बाद संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विश्वास किया गया है। इन समायोजनों का दावा अंतरदेशीय भाड़े एवं ऋण लागतों के संबंध में किया गया था और सत्यापन के दौरान सत्यापित कर लिया गया था, कारखानागत सामान्य मूल्य तय करने के लिए किया गया है।

थाईलैंड के सभी अन्य निर्यातक/ उत्पादक का सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड के किसी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने निर्यात की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस कारण से उनके मामलों में सामान्य मूल्य का निर्धारण रिकार्ड पर उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है।

चीन जन. गण. की निर्यात कीमत का निर्धारण

38. चीन जन. गण. के किसी निर्यातक ने निर्यात कीमत का ब्यौरा देते हुए कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराई है। इस कारण से प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के लेन देन वार आंकड़ों के आधार पर चीन जन. गण. के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, चीन जन. गण. के सभी निर्यातकों के संबंध में कारखानागत स्तर पर भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन खर्च, बैंक प्रभार, कमीशन और अंतरदेशीय भाड़े के लिए उचित समायोजन करने के बाद किया गया है।

थाईलैंड की निर्यात कीमत का निर्धारण

उत्तर देने वाले निर्यातक मैसर्स मेगोटेअक्स कं. लिमि., थाईलैंड के लिए निर्यात की कीमत

39. उत्तर देने वाले ने भारत में निर्यात से संबंधित परिशिष्ट 2 में सूचना उपलब्ध कराई है। इन समायोजनों का दावा समुद्री भाड़े, पत्तन रख-रखाव शुल्क, समुद्री भाड़ा और विदेशी बीमा जिसका सत्यापन के दौरान सत्यापित किया गया था, के आधार पर किया गया है और उसे निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

असहयोगी निर्यातक/ उत्पादक के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

40. चूंकि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक/ निर्यातक से कोई अन्य उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के 6(8) के संबंध में 'उपलब्ध तथ्यों' के अनुसार निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस आंकड़े का मिलान रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार किया गया है। तदनुसार, चीन जन. गण. के अन्य उत्पादक/ निर्यातक के संबंध में तथा थाईलैंड के उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित तालिका में तय की गई है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

41. अलग अलग संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है, जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

क्र. सं.	निर्यातक/ उत्पादक	सामान्य मूल्य यूएसडी/ मी. ट.	निर्यात मूल्य यूएसडी/ मी. ट.	पाटनरोधी यूएसडी/ मी. ट.	पाटनरोधी (%)	रेंज
1.	मैसर्स मेगोटेअक्स कं. लिमि. थाईलैंड	***	***	***	***	30-40
2.	थाईलैंड के सभी निर्यातक/ उत्पादक	***	***	***	***	30-40
3.	चाईना के सभी निर्यातक/ उत्पादक	***	***	***	***	0-10

क्षति का निर्धारण

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

42. घरेलू उद्योग ने संबद्ध ग्राइंडिंग मीडिया जॉर्ल्ड के सभी बाल्स के मामले में क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- ये उत्पाद भारतीय बाजारों में पाटित कीमतों पर लगातार आ रहे हैं : मौजूदा पाटनरोधी उपाय को वापस लिये जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को सतत पाटन और परिणामी क्षति होगी।
- घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले में क्षति का दावा नहीं किया है और यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को वर्तमान में लाभ प्राप्त हो रहा है, का संभावना की जांच तथा निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में कोई संबंध नहीं है।
- याचिकाकर्ता ने पहले ही यह सिद्ध कर दिया है कि निर्यातक पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने के बावजूद पाटित कीमतों पर भारत में इस उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए (2016-17 के लिए 33 प्रतिशत) ए आई ए का 44 प्रतिशत। ई बी डी टी ए जिसका दावा निर्यातक द्वारा किया गया है, का कोई आधार नहीं है।

क्योंकि इसमें अन्य गैर प्रचालन संबंधी आय और अन्य गैर विचाराधीन उत्पादों पर मार्जिन शामिल है, जो जी एम बाल की तुलना में बहुत अधिक है।

- iv. अनेक प्रकार के कास्टिंग होते हैं और कास्टिंग का उत्पादन करने वाली अन्य कंपनियों का कार्य निष्पादन तथा उसकी तुलना याचिकाकर्ता के कार्य निष्पादन से करना इस जांच में संगत नहीं है।
- v. यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का समाप्त करने के फलस्वरूप पाटन और मार्जिन की संभावना उत्पन्न होगी और इस कारण से शुल्क को जारी रखा जाना चाहिए, कानून द्वारा यथानिर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत है।
- vi. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद वर्तमान क्षति की अवधि में सुधार हुआ है। मौजूदा पाटन शुल्क हटाये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के अनुकूल बनाने के लिए अपनी कीमतों में कटौती करने के लिए बाध्य होगा।
- vii. ऐसी स्थिति में इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम होगी, घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन गिरकर उस स्तर पर पहुंच जायेगा जहां घरेलू उद्योग को समुचित से कम लाभ प्राप्त हो रहा होगा।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

43. घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - i. घरेलू उद्योग अत्यधिक और असामान्य लाभ अर्जित करता रहा है।
 - ii. ए आई ए द्वारा नियोजित पूंजी पर लाभ 22 प्रतिशत से अधिक है जो बैंचमार्क लाभ है।
 - iii. शिकायतकर्ता "सुधार से बहुत आगे हैं"।
 - iv. ए आई ए के निर्यात कारोबार में सतत रूप से वृद्धि हुई है और इस प्रकार से इसे सुरक्षा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
 - v. घरेलू उद्योग अब वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हो गया है और वास्तविक क्षति इसके होने की संभावना, का इसे कोई खतरा नहीं है।
 - vi. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ का संदर्भ लेने पर यह दावा किया गया था कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

44. यहां नीचे दिए गए प्राधिकारी द्वारा किये गए क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
45. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति के निर्धारण "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"
46. इस व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधीनियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा

क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

47. सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाये गये पाटनरोधी शुल्क, यदि इसे पूर्व में समाप्त नहीं किया गया हो, इस प्रकार के लगाये जाने की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगी बतर्श कि यदि केंद्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत हो कि इस प्रकार के शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके पीछे फिर से उत्पन्न होने की संभावना है, यह समय समय पर इस प्रकार से शुल्क लगाये जाने की अवधि को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा सकती है और इस प्रकार की बढ़ाई गई अवधि, इस प्रकार के बढ़ाये जाने के आदेश की तिथि से आरंभ होगी।
48. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध II (iv) के अनुसार ऐसे सूचकांकों पर विचार किया है, जिसका उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री की प्राप्ति, आकार और पाटन का मार्जिन आदि।
49. इस संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने की कार्यवाही करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो की जांच करने की कार्यवाही करते हैं।

(i) मांग का आंकलन/ स्पष्ट खपत

50. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को सभी स्रोतों से आयातों तथा भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में परिभाषित किया है।
51. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
मांग					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	96	103	106
अन्य भारतीय उत्पादों की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	100	100
चीन	मी. ट.	***	***	***	***
थाईलैंड	मी. ट.	***	***	***	***
संपूर्ण रूप में संबद्ध देश	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	550	299	241
अन्य देशों - आयात	मी. ट.	-	-	-	-
कुल मांग/ खपत	मी. ट.	54,032	53,346	55,067	55,937

52. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति की अवधि की तुलना में मांग में वृद्धि दर्शाई है।

(ii) पाटित आयातों का मात्रा का प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

53. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस पर विचार करें कि क्या भारत में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु से आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है।
54. निम्नलिखित तालिका में आयात की मात्रा और बाजार हिस्से के संबंध में वास्तविक स्थिति का सार दिया गया है :

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
-------	------	---------	---------	---------	---------

आयात – मात्रा					
संपूर्ण रूप में संबद्ध देश	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	550	299	241
अन्य देश	मी. ट.	-	-	-	-
कुल आयात	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	550	299	241
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयात					
खपत	%	0.19%	1.03%	0.54%	0.43%
कुल आयात	%	100%	100%	100%	100%
भारतीय उत्पादन	%	0.06%	0.29%	0.17%	0.11%

55. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी नीचे दिए अनुसार नोट करते हैं :

(क) आधार वर्ष से आयातों में वृद्धि हुई है।

(ख) यह भी नोट किया जाता है कि भारतीय मांग और खपत की तुलना में आयात कम रहा है।

(III) **घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की कीमत का प्रभाव**

(क) **कीमत में कटौती**

56. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में तमाम उत्पाद की कीमत से तुलना किये जाने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों बहुत अधिक सीमा तक मंदी होगी अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी, जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक बढ़ गई होती।

57. इस संबंध में, इस उत्पाद का पहुंच मूल्य और व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों का निवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच एक तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया था। प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है।

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	105	96
चीन (जी12)					
पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुंच कीमत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	100	99
कीमत में कटौती	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
कीमत में कटौती %	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती %	रेंज	0-10	0-10	10-20	0-10
थाईलैंड					
पाटनरोधी शुल्क बिना पहुंच कीमत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	109	92
कीमत में कटौती	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
कीमत में कटौती %	%	***	***	***	***

कीमत में कटौती %	रेंज	(0-10)	10-20	(0-10)	0-10
------------------	------	--------	-------	--------	------

58. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती हो रही है।

(ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

59. इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से की पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है अथवा उस पर दबाव बन रहा है और यह कि इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से कीमतों में बहुत अधिक सीमा तक कमी होगी अथवा कीमत में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि की तुलना में लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है। यह स्थिति नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शायी गई है :

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री की लागत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	97	86
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	105	96
पहुंच कीमत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	102	90

60. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात की कीमत क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत की तुलना में कम है।

(iv) घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदण्ड

61. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार के उत्पादों की घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों का घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन मात्रा; नकदी के प्रभाव, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों का एक वस्तुपरक और पक्षपात रहित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

62. तदनुसार, घरेलू उद्योग की विभिन्न आर्थिक मानदण्डों का विश्लेषण यहां नीचे किया गया है :

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा

63. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता का उपयोग नीचे दर्शाये गये अनुसार आगे बढ़ा है :

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
क्षमता	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	142	173
संयंत्र का उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	107	134
उत्पादन- विचाराधीन उत्पाद	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	106	133
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	75	78
-----------	----------	-----	----	----	----

64. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में स्वतंत्र रूप में सुधार हुआ है। हालांकि, इस संयंत्र की क्षमता के उपयोग में बहुत अधिक गिरावट आई है।

(ख) मांग में बाजार हिस्सा

65. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे दर्शाये गये अनुसार बढ़ा है :

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	50.77%	49.29%	51.33%	52.19%
अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	49.04%	49.68%	48.12%	47.37%
संबद्ध देशों के आयातों का हिस्सा	%	0.19%	1.03%	0.54%	0.43%
अन्य देशों के आयातों का हिस्सा	%	0%	0%	0%	0%
कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

66. उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि भारतीय उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा कुल मिलाकर पूरी क्षति की अवधि में समान रहा है। आयातों का बाजार हिस्सा उसी रेंज में रहा है।

(ग) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नगद लाभ

67. घरेलू उद्योग का लाभ, निवेश पर आय और नगदी के प्रभाव के संबंध में कार्य निष्पादन नीचे दिए गए अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
नगद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	745	813
व्याज	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	85	67
व्याज पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-219	685	811
नियोजित पूंजी पर लाभ -एन एफ ए	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-232	471	541

68. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का लाभ, नगद लाभ और नियोजित पूंजी पर लाभ में लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण क्षति की पूरी अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

(घ) माल सूची

69. घरेलू उद्योग के पास माल सूची नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
-------	---------	---------	---------	---------	--------------

औसत भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	126	228
प्रति दिन माल भंडार	मी. ट./ दिन	10	11	13	23
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	126	228

70. घरेलू उद्योग के माल भंडार के स्तर में इस पूरी अवधि के दौरान सतत् रूप से वृद्धि हुई है। प्रतिदिन माल भंडार में भी वृद्धि हुई है।

(ङ) रोजगार और मजदूरी

71. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिए गए अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	117	146
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	124	144
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. ट./ सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	90	91
प्रति दिन उत्पादकता	मी. ट./ दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	106	133

72. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं रोजगार और मजदूरी के स्तरों में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

पाटन की पद्धति

73. पाटनकी पद्धति उस सीमा का एक संकेतक है जिस सीमा तक पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारण किया गया पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

74. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कोई सूचना सत्यापन के योग्य नहीं है और न ही रिकार्ड पर उपलब्ध है जिससे यह अर्थ निकल सके कि इस क्षेत्र में भावी निवेश संबद्ध देश से पाटित आयातों की मौजूदगी से नष्ट हो सकती है।

क्षति की पद्धति और क्षति मार्जिन

75. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य से की गई है और इस प्रकार से तय की गई क्षति का मार्जिन नीचे दिया गया है।

क्षति मार्जिन की तालिका

क्र. सं.	निर्यात/ उत्पादक	क्षति रहित कीमत यू एस डी/ मी. ट.	पहुंच मूल्य यू एस डी/ मी. ट.	क्षति मार्जिन यू एस डी/ मी. ट.	क्षति मार्जिन (%)	रेंज
1.	मैसर्स मेगोटेअक्स क. लिमि., थाईलैंड	***	***	***	***	0-10
2.	थाईलैंड के सभी निर्यातक/ उत्पादक	***	***	***	***	0-10
3.	चीन के सभी निर्यातक/ उत्पादक	***	***	***	***	0 -10

पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना

76. प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का उद्देश्य किसी वर्तमान क्षति के न होने पर भी पाटनरोधी शुल्कों को यदि समाप्त होने दिया गया हो, तब सतत पाटन और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

77. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन के जारी रहने तथा परिणामी रूप से क्षति के फिर से उत्पन्न होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है :

- यद्यपि घरेलू उद्योग की स्थिति पाटनरोधी शुल्क के लगाये जाने के बाद स्थिर हो गई है परंतु संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताओं पर नजर डालने के बाद पाटन के फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की एक स्पष्ट संभावना है।
- लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप संबद्ध देशों से उत्पाद का गहन पाटन होगा। घरेलू उद्योग को क्षति से संभवतः पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में फिर से उत्पन्न होगी।
- लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण आयात की मात्रा में कमी आई है परंतु ये आयात पाटित कीमत पर हुए हैं।
- निर्यातक के पास पर्याप्त रूप से एवं स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताएं हैं और उनकी क्षमताओं को और आगे बढ़ाया गया है। कंपनी के सार्वजनिक विवरण के अनुसार उनके पास प्रतिवर्ष 140,000 ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स का उत्पादन करने की क्षमता है।
- संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग केवल 2900 मी. ट. प्रतिवर्ष है। पूर्व में निर्यातक की क्षमता 80,000 मी. ट. प्रति टन थी जो पहले संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की मांग से बहुत अधिक थी। इसके अलावा, पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने इसमें और आगे विस्तार किया है और उन्होंने अपनी क्षमता की घोषणा 140,000 मी. ट. प्रतिवर्ष के रूप में की है।
- घरेलू उद्योग ने यह दावा नहीं किया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। विभिन्न आर्थिक मानदण्डों ने पाटनरोधी शुल्क की सुरक्षा अम्ब्रेला के अंतर्गत सुधार दर्शाया है।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में सुधार हुआ है और वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दी गई सुरक्षा के कारण हुआ है और यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा पूर्व में उठाई गई क्षति पाटन के कारण हुई थी और उसका समाधान पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने के साथ हो गया है।
- घरेलू उद्योग का लाभ, नगद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के विकास में विभिन्न आर्थिक कारकों के संबंध में सुधार हुआ है।
- पाटन मार्जिन पिछले मामलों में अधिक रहा है।

- x. घरेलू उद्योग की स्थिति पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने के कारण सुधार हुआ है। संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की अतिरिक्त क्षमताओं और सीमित मांग पर नजर डालने के बाद, घरेलू उद्योग को पाटन के शुरू होने और परिणामी क्षति होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
- xi. बाजार में संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों की उपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार बहुत अधिक कीमत संवेदनशील है।
- xii. संबद्ध देशों से आयात बहुत अधिक गिरावट आई है परंतु भावी आयातों को पूर्ण रूप से इनकार नहीं किया जा सकता है जैसा कि वर्तमान आयातों से सिद्ध होता है तथा उनके द्वारा दिये गये ऑफर से सिद्ध होता है।
- xiii. पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती सकारात्मक है जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि पाटित आयातों के कारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के हटाये जाने की स्थिति में घरेलू कीमतों में कटौती होगी।
- xiv. जांच किए जाने वाले मुद्दे यह नहीं हैं कि क्या वर्तमान में पाटन हो रहा है अथवा घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ रही है बल्कि यह जांच करना है कि क्या शुल्कों को समाप्त किए जाने पर पाटन और क्षति के फिर से उत्पन्न होने की कोई संभावना है।
- xv. प्राधिकारी को मानदण्डों जैसे कि क्या पर्याप्त और स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य अथवा एक आसन्न, वास्तविक वृद्धि निर्यातक की क्षमता में हुई है और जो यह दर्शाता हो कि किसी अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बड़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना है, की जांच करने की आवश्यकता है।
- xvi. वर्तमान पाटन के न होने का यह आशय नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की कोई संभावना नहीं है। क्षति के न होने से यह निष्कर्ष निकालना पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- xvii. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता है जो यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में भविष्य में निर्यात और अधिक होगा।
- xviii. याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन भी सकारात्मक और अधिक है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, निर्यातकों को घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को लिये जाने के साथ भारत में विचाराधीन उत्पाद को पाटित करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्राप्त होगा।
- xix. संबद्ध देशों में उत्पादक संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारी मात्रा में क्षमताएं बनाये रखते हैं। मैसर्स मेगोटेअक्स क. लिमि. विचाराधीन उत्पाद का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका ग्राइंडिंग मीडिया और कास्टिंग के 500,000 टन से अधिक का बाजार फुट प्रिंट है।
- xx. संबद्ध देशों द्वारा कीमत में कटौती के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में और आगे कटौती करने के लिए बाध्य हो सकता है। इसके फलस्वरूप संबद्ध देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में ये निर्यात और अधिक होंगे।
- xxi. विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार बहुत अधिक कीमत संवेदनशील है; इस बाजार में संबद्ध देशों से इस प्रकार की कम कीमत पर आयातों की उपलब्धता के कारण निश्चित रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- xxii. भविष्य में पाटन की संभावना का भी पता इस तथ्य के आधार पर लगाया जा सकता है कि संबद्ध देशों से निर्यातों में बहुत अधिक गिरावट आई है जबकि वह सामान्य मूल्य से बहुत कम कीमत पर होता है।
- xxiii. पाटन की संभावना से संबंधित कारक क्षति की संभावना तथा वर्तमान मामले में संगत हैं। पाटन शुल्कों को लगाये जाने के बावजूद, आयातों पाटित कीमतों पर किए गए हैं।
- xxiv. वर्तमान जांच की अवधि में पाटन मार्जिन चीन जन. गण. के संबंध में सकारात्मक और बहुत अधिक है। जहां तक थाईलैंड का प्रश्न है, वहां कम मात्रा में पाटन हुआ है।
- xxv. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के बिना कीमत में कटौती सकारात्मक हुई है।

- xxvi. आयात कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, उपभोक्ता आयात किए गए उत्पादों का पसंद करेंगे जिसके फलस्वरूप आयात में वृद्धि होगी।
- xxvii. घरेलू उद्योग के पास पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी बिक्री कीमत में कटौती करनी पड़ेगी जिससे यह बिक्री की लागत से कम हो जायेगी; इसके फलस्वरूप बहुत अधिक कीमत क्षति होगी।
- xxviii. इन निर्यातकों के बदले हुए व्यवहार को पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने के परिणामस्वरूप देखा जा सकता है, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने पर पाटित कीमतों पर उत्पादों का निर्यात करने का अनुमान उचित रूप से नहीं लगाया जा सकता है।
- xix. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में समान रूप से स्थित स्थितियों में पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार की सिफारिश की है।
- xxx. इस प्राधिकारी के लिए पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने अथवा इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र कारक जिस पर विचार किया जाना है, वह पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति का फिर से उत्पन्न होना है।

अन्य हितवद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

78. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन के जारी रहने और क्षति के परिणामी रूप से फिर से उत्पन्न होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. प्राधिकारी को यह भी नोट करना चाहिए कि यदि वे शुल्क के जारी रहने की संभावना का निर्धारण करते समय पाटन मार्जिन पर भरोसा करते हैं तब वह अनुच्छेद 2.4 की परिधि के अंतर्गत किया जाना चाहिए और क्षति का निर्धारण 'सकारात्मक साक्ष्य' और एक 'वस्तुपरक जांच' के आधार पर होना चाहिए।
- ii. सकारात्मक साक्ष्य मौजूद नहीं है, के फलस्वरूप उचित रूप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति की संभावना है।
- iii. शिकायतकर्त्ता क्षति की संभावना को सिद्ध करने के संबंध में तर्कपूर्ण साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराने में असफल हुआ है।
- iv. घरेलू उद्योग मुख्य रूप से मैसर्स ए आई ए इंजीनियरिंग लिमि. की क्षमता इस बात को उजागर करते हुए अंतिम जांच की जांच अवधि के बाद बढ़ी है कि इस उद्योग पर कोई क्षतिकारक प्रभाव नहीं पड़ा है और इस प्रकार से क्षति की संभावना नहीं है। शिकायतकर्त्ता ने इन सभी तीन वर्षों में क्षमता में विस्तार किया है।
- v. शिकायतकर्त्ताओं ने अपने आप इसकी पुष्टि की है कि 4,40,000 मी. ट. की रेट की गई क्षमता का विस्तार करने के बाद वे केवल भारत में नहीं बल्कि स्वेच्छिक रूप में ग्राइंडिंग मीडिया का सबसे बड़ा उत्पादक हो जायेगा।
- vi. जांच की अवधि के दौरान थाईलैंड से जी एम बालक का आयात 186 मी. ट. है जो शिकायतकर्त्ता की संस्थापित क्षमता का 0.05 प्रतिशत से कम है जो इस बात को निर्धारित करता है कि आयात की इस प्रकार की राशि से घरेलू उद्योग को कभी भी क्षति नहीं हो सकती है।
- vii. घरेलू उद्योग बहुत अधिक और असामान्य लाभ अर्जित करता रहा है (तालिका दी गई है)।
- viii. निम्नलिखित तथ्यों को याचिका में गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है :
 - क. मेगोटेअक्स कं. लिमि. थाईलैंड अपने प्रतिष्ठानों और एसोसिएट के माध्यम से उत्पादन की लागत पर दबाव बना रहा है। इस संबंध में निर्यातक ने यह दावा किया कि यह एक गलत आरोप है और शिकायतकर्त्ता माननीय प्राधिकारी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।
 - ख. मेगोटेअक्स और घरेलू उद्योग की संस्थापित संस्था के संबंध में तथ्य गलत हैं। संपूर्ण संस्थापित संस्था क्षमता का उपयोग एशिया प्रशांत बाजार और न केवल भारत की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

79. प्राधिकारी ने क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना की जांच इस नियमावली के अनुबंध II नियम (vii) के संबंध में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदण्डों पर विचार करते हुए की। इस नियमावली के अनुबंध II के नियम (vii) में निम्नलिखित प्रावधान है :

(क) पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात किए जाने की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की एक अत्यधिक दर

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयात- मात्रा					
संपूर्ण रूप में संबद्ध देश	मी. ट.	***	***	***	***
अन्य देश	मी. ट.	-	-	-	-
कुल आयात	मी. ट.	***	***	***	***
कुल आयात	प्रवृत्ति	100	550	299	241

80. प्राधिकारीयह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के साथ, संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। हालांकि, भारतीय बाजार में अब भी आयात हो रहे हैं। ऐसी संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा विदेशी उत्पादकों की अनुपयुक्त क्षमताओं पर विचार करते हुए और बढ़ेगी।

(ख) पर्याप्त और स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य अथवा एक आसन्न, वास्तविक वृद्धि निर्यातक की क्षमता में और जो यह दर्शाता हो कि किसी अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना है।

81. वास्तविक क्षति के खतरे का पता लगाने लगाने के लिए इस मानदण्ड में मौजूदा अतिरिक्त क्षमताओं और क्षमतावर्धन, यदि कोई हो, का मूल्यांकन अपेक्षित है ताकि भारतीय बाजार में बिक्री के योग्य मात्रा को परिवर्तित किए जाने की संभावना तलाश की जा सके। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में इन उत्पादकों को पहले बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा, इन उत्पादकों ने यह स्वीकार किया है कि वे इस उत्पाद को अनेक देशों में निर्यात कर रहे हैं, वर्तमान में एक बहुत छोटे अनुपात में निर्यात भारत में किया जा रहा है। इसका निर्यात उस कीमत पर किया जा रहा है, जो भारत के संबंध में प्रचलित कीमतों से कम है और इस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने की स्थिति में भारत में इन निर्यातों को परिवर्तित किये जाने की संभावना को दर्शाता है। घरेलू उद्योग ने थाईलैंड में वर्तमान मांग के संबंध में सूचना और निर्यातक द्वारा हाल में किये गये विस्तार को दर्शाते हुए एक वेब आर्टिकल की प्रतियां प्रस्तुत की हैं, उसे रिकार्ड पर ले लिया गया है।
82. मैसर्स मेगोटेअक्स कं. लिमि., थाईलैंड द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर और निर्यातक के वेबसाइट से घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर यह देखा जा सकता है कि मेगोटेअक्स के पास बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन क्षमताएं हैं। वे पूरे विश्व में ग्राइंडिंग मीडिया का निर्यात भी कर रहे हैं। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने न तो इस सूचना का विरोध किया है अथवा कोई प्रतिरोधी वास्तविक सूचना उपलब्ध कराई है। उत्तरदाता निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर का विश्लेषण यह दर्शाता है कि निर्यातक ने प्रश्नावली में निर्धारित किए गए अनुसार अपने तीसरे देशों के निर्यात के लेन-देन वार आंकड़ों के संबंध में निर्धारित स्वरूप और तरीके में सभी संगत सूचना प्रदान नहीं की है और इसीलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के आधार पर विश्लेषण किया है। ये क्षमताएं अपने आप में कुल मांग और तीसरे देश को किए गए निर्यात से अधिक है और इस पर विचार स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार की भारी उत्पादन क्षमताओं और उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा निर्यात के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। थाईलैंड के निर्यातक ने भी इस तथ्य के बावजूद क्षमताओं में विस्तार किया है कि मौजूदा क्षमताएं निर्यात करने वाले देश की कुल मांग से बहुत अधिक थी।

(ग) क्या निर्यात उन कीमतों पर हो रहा है जिसका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक न्यूनकारी अथवा दमनकारी प्रभाव पड़ेगा और संभवतः आगे आयात के लिए मांग में वृद्धि होगी।

83. भारत में वर्तमान पहुंच कीमत पर, लागू पाटनरोधी शुल्क के बिना जांच की अवधि के दौरान कीमत में सकारात्मक कटौती हुई है। हालांकि, इन आयातों का घरेलू कीमतों पर कोई न्यूनकारी अथवा दमनकारी प्रभाव नहीं पड़ता है।

(घ) उस वस्तु का माल भंडार जिसकी जांच की जा रही है।

84. निर्यातक द्वारा निर्यातक की प्रश्नावली में थाईलैंड के निर्यातक द्वारा दिए गए व्यौरे के अनुसार, माल भंडार में आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद जो बहुत अधिक मांग पर निर्भर करता है, कि प्रकृति के बावजूद माल भंडार में वृद्धि होती रही है।

ट. कारणात्मक संबंध

85. धारा 9क (5) के अंतर्गत, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात पर विचार किए बिना शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता तथा पाटन एवं क्षति की संभावना की जांच करे कि क्या समीक्षा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात हुआ है या नहीं। यह जांच किया गया था कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य मानदण्डों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था। इसे नीचे दिए गए अनुसार नोट किया जाता है।

(क) आयातों की मात्रा और मूल्य जिन्हें पाटित कीमतों पर नहीं देखा जाता है:

86. विभिन्न देशों से आयातों का विवरण यह दर्शाता है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं हुआ है। इस कारण से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भी क्षति हुई है।

(ख) मांग में संकुचन और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

87. संबद्ध देशों की मांग में क्षति की अवधि की तुलना में वृद्धि हुई। ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कारण से खपत की पद्धति में परिवर्तनों के कारण घरेलू उद्योग का क्षति नहीं हुई होगी।

(ग) विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा

88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास

89. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स के उत्पादन के प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कारण से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन क्षति का एक कारक नहीं है।

(ङ) निर्यात निष्पादन

90. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। हालांकि, उन्होंने घरेलू प्रचालनों में क्षति का दावा नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने पृथक् रूप से घरेलू बिक्री के लिए लागत और क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। इस कारण से घरेलू बिक्री को क्षति का कारण इन निर्यातों को नहीं माना जा सकता है।

(च) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए और बिक्री किए गए अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

91. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में इस अवधि की तुलना में सुधार हुआ है और ऐसा पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के कारण हुआ है।
92. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर इन जांचों की प्रक्रिया के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथा प्राप्त की गई, विश्लेषण की गई और सिद्ध की गई जांच के आवश्यक तथ्यों को एतद् द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया जाता है, जिससे कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथाउल्लिखित इन तथ्यों के संबंध में अपनी टिप्पणियां देने के लिए सक्षम हो सकें।

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

93. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उनमें उठाए गए मुद्दों को जांच के दौरान पहले ही उठा दिया गया है और उनका उपयुक्त रूप से समाधान भी किया गया है। तथापि, स्पष्टता के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की जा रही है:

घरेलू उद्योग के विचार

- प्रकटन संबंधी पत्राचार निर्यातक को भेजा गया और आरंभिक प्रश्नावली के उत्तर को दायर करने के बाद उनके द्वारा उत्तर दायर किए गए। यदि उसमें कुछ गोपनीय है तो हम उसके एनसीवी के प्रकटन के लिए अनुरोध करते हैं।
- याचिकाकर्ता (क) निर्यातक की सत्यापन रिपोर्ट (एनसीवी), (ख) निर्यातकों के साथ किए गए पत्राचार (एनसीवी), (ग) आरंभिक प्रश्नावली के उत्तर को दायर करने के बाद निर्यातक द्वारा दायर की गई सूचना का एनसीवी रूपांतर प्रकट करने का अनुरोध करते हैं।
- प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में क्षति नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में वर्तमान मामला संभावना/खतरे की जांच के आधार पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में संभावना का विश्लेषण क्षति मार्जिन पर आधारित न हो क्योंकि क्षति मार्जिन का उद्देश्य पाटनरोधी शुल्क की मात्रा निर्धारित करना ही है। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी की परिपाटी भी है जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उस समय पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन नहीं किया है जब निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया कि उसे जारी रखने अथवा आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्षति की संभावना के आधार पर है।
- पिछले दो वर्षों से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में काफी गिरावट आई है और विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत नाटकीय रूप से बढ़ी है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबद्ध देशों के निर्यातों ने जान-बूझकर कीमतें और पाटनरोधी शुल्क की

- वापसी की मांग करने के लिए अपने निर्यात की मात्रा बनाई है और यदि वह कार्य नहीं करता तो निर्णायक समीक्षा जांच पर प्रभाव डालता है।
- v. वर्तमान में भारतीय बाजार में आने वाला आयात पूर्व स्तरों का केवल 2 प्रतिशत है, अतः इन आयातों के आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्यातक के संभावित व्यवहार का अत्यधिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते।
 - vi. उत्पादकों ने स्वीकार किया है कि वे अधिसंख्य देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं, वर्तमान में बहुत कम अनुपात में भारत को निर्यात किया जा रहा है जो भारत के संबंध में कीमतों से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्पादक भारत में कीमत से कम कीमत पर अन्य देशों में उत्पाद की बिक्री कर रहा है।
 - vii. पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में उत्पादक अपना भारत में तीसरे देशों से निर्यात की ओर जाएंगे क्योंकि वे भारतीय बाजार में बेहतर कीमतें देने में सक्षम होंगे और उत्पाद का पाटन करने में भी सक्षम होंगे। प्राधिकारी द्वारा सही उल्लेख किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में इन आयातों के भारत में आने की संभावना है।
 - viii. निर्यातकों के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमताएं हैं। ये क्षमताएं कुल मांग और तीसरे देशों के निर्यात से अपने-आप में अधिक हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमताओं के रूप में माना जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्यातकों के पास क्षमताएं मांग और तीसरे देशों को निर्यात से केवल अधिक नहीं हैं। ये अतिरिक्त क्षमताएं पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के लिए उपयोग में लाए जाने की संभावना है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
 - ix. थाइलैंड के निर्यातक ने भी इस तथ्य के बावजूद क्षमताएं बढ़ाई हैं कि मौजूदा क्षमताएं निर्यातक देश की कुल मांग से कहीं अधिक थीं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्वतंत्र निपटान योग्य क्षमताओं के बावजूद निर्यातक अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारत को निर्यात पाटित कीमतों पर बढ़ने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
 - x. कीमत कटौती सकारात्मक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने के बावजूद ये आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर थे। जैसा कि प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण के पैरा 82 में नोट किया गया है।
 - xi. प्रकटन विवरण के पैरा 83 में निर्यातकों की मालसूची यह दर्शाती है कि प्राधिकारी ने नोट किया है कि निर्यातक की मालसूची लगातार बढ़ी है। यह उत्पाद के मांग संचालित होने के बावजूद है।
 - xii. निर्यातक की बढ़ती हुई मालसूची, स्वतंत्र निपटान योग्य क्षमताएं और निर्यातक की विस्तार योजनाएं उन्होंने स्वयं स्वीकार की हैं और यह दर्शाता है कि पाटित आयातों की मात्रा बढ़ेगी तथा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
 - xiii. यद्यपि याचिकाकर्ता मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध करते हैं, तथापि, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क अमेरिकी डॉलर/किलोग्राम में व्यक्त पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा (शुल्क का निर्धारित स्वरूप) के रूप में लगाया जाए।
 - xiv. क्षति रहित कीमत का निर्धारण उचित नहीं है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- i. प्राधिकारी को मूल गैर अधिमान्य नियमों पर लागू सीमा शुल्क पर विचार करना चाहिए न कि आसियान करार के तहत अधिमान्य शुल्क पर। कोरिया से फॉस्फोरिक एसिड के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिमान्य शुल्क की उपेक्षा की और शुल्क की मानक दर अपनाई।
- ii. यह अनुरोध है कि शिकायतकर्ता तथा निर्यातक, दोनों एक ही बाजार (एशिया, पसिफिक, अफ्रीका और अमेरिका) में उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। शिकायतकर्ता और निर्यातक, दोनों ने निर्यात के लिए लेन-देन वार आंकड़े दिए हैं और इसीलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के संबंध में अपेक्षित सूचना है। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उत्पादन लागत और अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करना चाहिए और शिकायतकर्ताओं की वसूल की गई बिक्री कीमत पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
- iii. यह दर्शाने के लिए कई बीजक प्रस्तुत किए गए हैं कि घरेलू उद्योग पहुँच मूल्य से कम कीमत पर उत्पाद की बिक्री कर रहा है।
- iv. ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आयात की पहुँच कीमत का तुलनात्मक विश्लेषण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ करके 0-10 प्रतिशत की कीमत कटौती परिकलित की है।
- v. घरेलू उद्योग का नकद लाभ आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 8 गुना तक बढ़ा है। लाभप्रदता 40 प्रतिशत तक बढ़ी है जबकि कास्टिंग उद्योग की लाभप्रदता केवल 17-18 प्रतिशत है।
- vi. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण/ह्रास आदि का परिकलन सकल आधार पर किया है। इस संबंध में यह अनुरोध है कि विचाराधीन उत्पाद आधार क्रोम की मात्रा तथा आकार के भिन्न-भिन्न ग्रेड हैं। इसके अतिरिक्त, अंतिम प्रयोक्ताओं के रूप में भी भिन्न-भिन्न ग्रेडों की भिन्न-भिन्न उत्पादन लागत, कच्ची सामग्री का सम्मिश्रण है। यह अनुरोध है कि पक्षकारों ने ग्रेड-वार आंकड़े दिए हैं। तदनुसार, यह अनुरोध है कि क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन और इसी के

समान अन्य मार्जिन का निर्धारण अथवा तुलना अलग-अलग ग्रेडों के आधार पर होनी चाहिए न कि सकल स्तर आधार पर। सकल स्तर समग्र निर्णायक समीक्षा कार्यवाही को खराब कर देता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

94. भारत और थाइलैंड के बीच करार के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी ने लागू सीमा शुल्कों के अनुसार पहुँच मूल्य का मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक ओर अधिमान्य व्यापार करार के प्रावधान पहुँच मूल्य को कम कर सकते हैं, परंतु इसके साथ ही निर्यातक अन्य प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में निर्यात कीमत में शून्य आयात शुल्क के लाभ को कारक बनाकर अपनी निर्यात वसूली बढ़ाने के लिए इसे बढ़ा सकते हैं जिससे एक ओर किसी सीमा तक पहुँच मूल्य में वृद्धि होगी तथा निर्यात कीमत में वृद्धि के कारण पाटन मार्जिन कम होगा। अतः इन पहलुओं का समायोजन किए जाने की भी आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी ने लागू सीमा शुल्कों के साथ पहुँच मूल्य का मूल्यांकन करने की अपनी सतत परिपाटी अपनाई है।
95. प्राधिकारी यह पाते हैं कि निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि निर्यात घरेलू कीमत से अधिक कीमत पर किए गए हैं और इसके साथ ही उसने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक लाभ अर्जित किया है तथा उसकी लाभप्रदता में सुधार आया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने खुद यह दावा नहीं किया है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सतत रूप से क्षति हो रही है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि निरंतर पाटन होने की प्रबल संभावना है तथा परिणामस्वरूप उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। चूंकि, वर्तमान जांच पाटन की संभावना/बार-बार होने के खतरे पर आधारित है, अतः वास्तविक क्षति से संबंधित वास्तविक मानदंड पर्याप्त रूप से संगत नहीं हैं।
96. इस तर्क के संबंध में कि क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उत्पादन लागत की तुलना अंतर्राष्ट्रीय कीमत से की जानी चाहिए तथा घरेलू उद्योग की वसूल की गई कीमतों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी ने निबल बिक्री वसूली पर विचार किया है और उसकी तुलना आयातों की पहुँच कीमत से की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने एनआईपी की तुलना आयातों की पहुँच कीमत से की है। यह तर्क कि याचिकाकर्ता कई देशों को तुलनीय कीमतों पर भी निर्यात कर रहा है, क्षति निर्धारण की वर्तमान संभावना के क्षेत्र से बाहर है।
97. यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने घरेलू बिक्री में या तीसरे देशों के निर्यात में शामिल उत्पाद किस्म की पर्याप्त रूप से पहचान नहीं की है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि उत्पाद की लागत और कीमत क्रोम की मात्रा तथा बॉलों के आकार में भिन्न-भिन्न है। तथापि, निर्यातक ने आयातों की पहचान करने तथा उन्हें पृथक् करने के लिए संगत विचार के रूप में बॉल के आकार की पहचान नहीं की है। यह भी नोट किया जाता है कि निर्यातक ने उन सभी ग्रेडों के लिए उत्पादन लागत नहीं दी है जो निर्यातक ने घरेलू बाजार में बेचे हैं अथवा तीसरे देशों को निर्यात किए हैं। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने प्राधिकारी को सभी संगत सूचना प्रदान न करने का निर्णय स्वयं लिया है और उत्पाद को आंशिक रूप से भिन्न-भिन्न किस्मों में पृथक् किया है। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी के पास एकमात्र विकल्प भारित औसतों के आधार पर कार्यवाही करने का है।
98. ग्रेड-वार पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उत्तरदाता निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में इसके लिए अपेक्षित आंकड़े नहीं दिए हैं। न ही मौखिक साक्ष्य के दौरान भी विभिन्न उत्पाद किस्मों के लिए दिए जाने हेतु अपेक्षित पृथक् सूचना के संबंध में प्राधिकारी से कोई स्पष्टीकरण मांगा है तथा केवल प्रकटन पश्चात टिप्पणियों के स्तर पर मुद्दा उठाया है। यह उस तथ्य के बावजूद है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्नावली स्पष्ट रूप से निर्यातकों से यह अपेक्षा रखती है कि वे विभिन्न उत्पाद किस्मों के लिए अलग सूचना दें। इसके अतिरिक्त, टेबल सत्यापन के दौरान भी यह सूचना तैयार रूप में नहीं दी गई थी और उसे अनुस्मारक के माध्यम से मंगाया गया था। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने ग्रेड-वार निर्धारण के लिए प्राधिकारी को सभी संगत सूचना न देने का सजग विकल्प लिया। पूरी तरह से अपर्याप्त निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की स्थिति में प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना से भारित औसत के आधार पर कार्यवाही की है।
99. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयात की मात्रा पूर्ण दृष्टि से अथवा उत्पादन एवं खपत के संबंध में काफी कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता ने स्वयं दावा नहीं किया है कि आयातों से वास्तविक क्षति हो रही है, न ही प्राधिकारी ने क्षति जारी रहने के आधार पर मामले की जांच की। वर्तमान जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। चूंकि, प्राधिकारी को वर्तमान मामले में क्षति के बार-बार होने का निर्धारण करने की अपेक्षा है, अतः किसी भी दशा में आयात की वास्तविक मात्रा क्षति की संभावना के विश्लेषण के लिए पूर्ण संगत सूचना नहीं है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि निर्यातक के अधिसंख्य देशों को उत्पाद के बहुत ही अधिक निर्यात हैं, जैसा कि निर्यातक द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के व्यौरों से जांच की गई।

भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

100. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लगाने से पाटन की परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार

में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी तरह संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए ग्राहकों को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

निष्कर्ष

101. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन के बार-बार होने एवं परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- क. यदि लागू पाटनरोधी शुल्क प्रचालित होने बंद हो जाएं तो संबद्ध सामान भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आने की संभावना है।
- ख. यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बंद करने की अनुमति दी जाती है तो घरेलू उद्योग की स्थिति बिगड़ने की संभावना है।
- ग. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास होने की संभावना है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

सिफारिशें

102. यह निष्कर्ष निकाले जाने पर कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बंद करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन एवं क्षति के बार-बार होने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में उपाय बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
103. लागू वर्तमान उपाय की समाप्ति की स्थिति में पाटन एवं क्षति के आसन्न होने की संभावना की जांच करने पर प्राधिकारी भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1 खंड-I में प्रकाशित 22 मई, 2012 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना द्वारा प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार तथा दिनांक 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 36/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।
104. इस सिफारिश के कारण उत्पन्न होने वाली केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2018

(Final Findings)

Subject: Sunset review investigation concerning imports of 'Grinding Media Balls' (excluding Forged Grinding Media Balls) originating in or exported from China PR and Thailand.

BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 7/7/2017-DGAD.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of " 'Grinding Media Balls' (excluding Forged Grinding Media Balls)", (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Thailand (hereinafter referred to as subject Countries). The Authority vide its final findings No 14/34/2010-DGAD dated, 22nd May 2012 recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the Subject countries. Duties were imposed by the Central Government vide custom notification No. 36/2012-Customs (ADD) dated the 16th July, 2012.

2. Whereas, in terms of Section 9 A (5) the Customs Tariff Act, 1995, read with Rule 23 of the Rules, the antidumping duty imposed under the said Act shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, unless in a review, initiated before the expiry of the duty, the Designated Authority concludes that the cessation of the duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by

or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And Whereas a petition has been filed by the major domestic producer of Grinding Media Balls i.e., M/s AIA Engineering Ltd and M/s Welcast Steels Ltd, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from the countries/territories named above and consequent injury to the domestic industry and requesting for initiating sunset review investigation for continuation of anti-dumping duties in force on imports of Grinding media balls originating in or exported from China PR and Thailand.
4. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the Domestic Industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority issued a Notification No. 7/7/2017-DGAD dated 4th July, 2017, published in the Gazette of India, initiating a sunset review investigation in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, to review the need for continued imposition of the duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 15th July, 2018 vide Notification No. 34/2017-Customs (ADD) dated 13th July, 2017.
5. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from China PR and Thailand.

GENERAL PROCEDURE

6. Procedure described below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:
 - i. The Authority notified the Embassy/Representatives of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject countries in India, known producers/exporters in the subject countries, known importers/users in India, and the Domestic Industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters in subject countries and to the Embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - iv. The Embassy of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from China and Thailand to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from China PR and Thailand.
 - v. The Authority sent Exporter's Questionnaire to elicit relevant information to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. M/s Magotteaux Co. Ltd, Thailand
 - b. M/s Magotteaux Alloyed Material (Suzhou) Co.Ltd, China
 - vi. In response to the above notification, only M/s Magotteaux Co. Ltd, Thailand responded to the questionnaire issued by the Authority.
 - vii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. ACC Limited
 - b. Century Cement
 - c. Grasim Industries
 - d. Chariot Steel and Power (P) Ltd.
 - e. Alcon Cement Company
 - f. Chowgule and Co.
 - g. Ambuja Cement Co.

-
- h. Chunar Churk Cement Ltd.
 - i. Andhra Cement Co. Ltd.
 - j. Cement Manufacturing Co. Ltd.
 - k. Durga Cement Works
 - l. Shree Digvijay Cement
 - m. Anjani Portland Cement Ltd.
 - n. Deccan Cement Ltd. (002)
 - o. Asian Cement and Concrete
 - p. Diamond Cements
 - q. Bharat Heavy Electricals Ltd.
 - r. Eco Cement India Ltd.
 - s. Binani Cement Ltd.
 - t. Green Valliey Industries Pvt. Ltd.
 - u. Birla Corporation Ltd.
 - v. Gujarat State Electricity Corp.
 - w. Gujarat Sidhee Cement Ltd.
 - x. Panipath Thermal Power Station
 - y. Hindalco Industries Ltd (Dahej)
 - z. Humboldt Wedag India Pvt Ltd. (Cement Division)
 - aa. Hindustan Zinc Ltd.
 - bb. India Resources Ltd.
 - cc. The India Cement Ltd.
 - dd. J K Cement Works
 - ee. Jaiprakash Associates Ltd.
 - ff. Jindal Steel Power Ltd.
 - gg. Jaypee Rewa Plant
 - hh. JK Laxmi Cement Ltd.
 - ii. J K White Cement Works
 - jj. Jaiprakash Associates Ltd.-Chunar
 - kk. Kakatiya Cement Sugar & Industries
 - ll. Keerthi Industries Ltd.- Mellac
 - mm. Khyber Industries (P) Ltd. – Kashmir
 - nn. Kesoram Cements - Basantnagar
 - oo. Lafarge India Pvt Ltd - Arasmata
 - pp. Madras Cements Ltd - Jayathipuram
 - qq. Maihar Cement
 - rr. Mahi Cement (A Unit of Indo Zinc Limited)
 - ss. Manikgarh Cement (A Divn of Century Textiles & Inds Ltd.)
 - tt. Mandovi Pellets (A Divn. Of Chowgule & Company Ltd.),
 - uu. Meghalaya Cements Limited
 - vv. Megha Technical & Engineers Pvt Ltd.

- ww. MSP Steel & Power Ltd. (Pellet Plant)
 - xx. Murli Industries Limited
 - yy. Maharashtra State Power Generation
 - zz. My Home Cement Industries Ltd-Mella
 - aaa. Ocl India Limited - Rajgangpur
 - bbb. Heidelberg Cement India Ltd.
 - ccc. Orient Cement - Devapur
 - ddd. NCL Industries Limited - Mattapally
 - eee. NGS White Cement Company
 - fff. Panyam Cements & Mineral Industries
 - ggg. Penna Cement Industries Ltd.
 - hhh. Parasakti Cement Industries Limited
 - iii. Sagar Cements Limited - Mattampally
 - jjj. Prism Cement Limited
 - kkk. Saurashtra Cement Limited
 - lll. Rain Commodities Ltd - Kurnool
 - mmm. Shiva Cement Limited
 - nnn. Rashmi Cement Limited (Cement Division)
 - ooo. Shree Cement Ltd. - RAS (SCR)
 - ppp. Reliance Infrastructure Ltd.
 - qqq. Trinayani Cement (P) Ltd.
 - rrr. Shriram Cement Works (A Division of DCM Shriram Consolidated Ltd.)
 - sss. Trumboo Industries Private Limited
 - ttt. Ultratech Cement Limited - AP
 - uuu. Tata Chemicals Ltd. – Mithapur
 - vvv. U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
 - www. Zuari Cement Ltd. - Yerraguntla
 - xxx. Vasavadatta Cement - Sedam
 - yyy. Penna Cement Industries Limited
 - zzz. Prism Cement Ltd. - Unit - Ii
 - aaaa. Sarda Energy & Minerals Limited
 - bbbb. Suday Minerals & Chemicals (P) Ltd.
 - cccc. Saloni Industries
 - dddd. Samruddhi Cement Limited
- viii. In response to the questionnaire issued by the Authority, only following responded to the importer's questionnaire response:
- a. Birla Shakti Cement
- ix. Further, the following interested party had filed response to the initiation of the investigation:
- a. My Home Industries Pvt. Ltd- Maha Cement
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- xii. The Non-Injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xiii. The Authority held an oral hearing on 16th March, 2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6), which was attended by the representatives of Domestic Industry, the responding exporter, importers and importers' association. The representatives who presented their views orally at the time of oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by opposing interested parties.
- xiv. Table verification of the data of the Domestic Industry and exporter questionnaire response was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this finding.
- xv. The period of investigation for the purpose of the present review is April 2016-March 2017 as the Period of investigation. The injury investigation period has however, been considered as the period 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the period of investigation.
- xvi. A Disclosure Statement was issued on 30th May, 2018 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 6th June, 2018 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xvii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this document.
- xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- xx. “***” in this findings represent information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.67.95= 1 US\$.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Views of the Domestic Industry

7. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:
 - i. The product under consideration in the present petition is the same as the original investigations, which can be defined as “The product under consideration is ‘Grinding Media Balls’ (excluding Forged Grinding Media Balls). ‘Grinding Media Balls’ (in short, ‘GM Balls’) are produced in different sizes, shapes and compositions for use in diverse applications. Further, it is available in different hardness depending upon varying requirements of the customers.”
 - ii. Grinding Media Balls are available in different sizes, shapes and compositions for use in diverse applications. They are available in different hardness as per customer specific requirement. Grinding media balls are used in ball mill for crushing and grinding heavy and hard materials.
 - iii. Grinding media balls (also known as Casting balls) are extensively used in grinding mills for grinding and crushing of limestone and clinker in Cement plants, mineral ore in mines and coal in thermal power plants.

- iv. Grinding media are cast in high chrome metallurgy which offers a longer wear life without risk of failure/breakage. High chrome cast balls have uniform wear profile which ensures consistent output for the grinding mills in which they are used.
- v. Grinding Media balls are produced in different sizes starting from 12 MM to 110 MM. It is also produced in different chrome content such as G12, G14, G15, G18, G21, G22 etc. In G12, 'G' stands for Grinding Media and '12' shows the quantity of Chrome content. Different sizes of balls are used for different purposes; for example, G12 is used in cement grinding with ball size of 50 to 90 MM.
- vi. For the purpose of fair comparison between the imported product and domestic product and for normal value and export price, petitioners suggest differentiation of different product types. Accordingly, the petitioners have segregated the information on product types.
- vii. The product under consideration is extensively used in cement build materials, metal mine, coal slurry, thermal power plant, chemical engineering, ceramic industry, dope industry, light industry such as papermaking and magnetic material etc. for powder preparation. The subject goods are classified under Customs sub-heading 7325 9100 of Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.
- viii. There is no difference in the technology employed and the quality of the domestic and imported product and are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Present investigation is a review investigation. The Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the original investigation, which is relied upon.
- ix. Each of the subject grinding media ball produced by the Domestic Industry is individually comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods with each of the subject grinding media balls imported from respective subject countries.
- x. Present investigation is a review investigation. The Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the original investigation, which is relied upon.

Views of the Interested Parties

8. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

Examination of the Authority

9. The products on which the duties are in force are Grinding Media Balls (excluding Forged Grinding Media Balls). This review covers the entire product and hereinafter they have been referred to as subject goods.
10. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject countries, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original and subsequent review investigations. The product under consideration defined in the previous investigations is as follows
 - 'Grinding Media Balls' (in short, 'GM Balls') are produced in different sizes, shapes and compositions for use in diverse applications. Further, it is available in different hardness depending upon varying requirements of the customers."
 - The product under consideration is extensively used in cement build materials, metal mine, coal slurry, thermal power plant, chemical engineering, ceramic industry, dope industry, light industry such as papermaking and magnetic material etc. for powder preparation. The subject goods are classified under Customs sub-heading 7325 9100 of Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.
11. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject countries and the product produced by the Indian industry. The subject product produced by the domestic industry is comparable to the Product under consideration in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
12. Thus, the Authority holds that the subject product produced by the applicant domestic industry is like article to the Product under consideration, in accordance with the Anti Dumping Rules.

SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**Views of the Domestic Industry**

13. Following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to scope and standing of the Domestic Industry:
- The present petition is being filed by AIA Engineering Ltd and Welcast Steels Ltd, who produce the subject goods in India for review and continuation of the quantum of anti-dumping duty in force on imports of Grinding Media Balls originating from Thailand and China PR.
 - The petitioner alone commands majority proportion in Indian production. It has neither imported the subject goods nor is related either to any exporter of the subject product in subject countries or an importer in India.
 - No published information is available with regard to the production of the other Indian producers. The petitioner has determined the production of other Indian producers based on their imports of raw materials, domestic sales, imports and exports made by individual Companies.

Views of the other Interested Parties

14. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to scope and standing of the Domestic Industry:
- None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

Examination of the Authority

15. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

16. The application has been filed by AIA Engineering Ltd and Welcast Steels Ltd. The statement of Indian production is as follows:

S. No.	Name of unit	UOM	Particulars			
			2013-14	2014-15	2015-16	POI
1	Petitioner Companies					
a	AIA Engineering Ltd.,	MT	***	***	***	***
b	Welcast Steels Ltd.	MT	***	***	***	***
c	Total of Petitioner companies	MT	***	***	***	***
2	Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
a	Total Indian Production	MT	1,66,618	1,90,021	1,74,349	2,13,292
S. No.	Name of unit	UOM	Share (%)			
			2013-14	2014-15	2015-16	POI
1	Petitioner Companies					
a	AIA Engineering Ltd.,	%	61%	69%	73%	70%
b	Welcast Steels Ltd.	%	23%	17%	12%	17%
c	Total of Petitioner companies	%	84%	86%	85%	88%
2	Other Indian Producers	%	16%	14%	15%	12%
a	Total Indian Production	%	100%	100%	100%	100%

17. The Authority notes, on the basis of information on record the petitioner accounts for 88% for total Indian production and accounts for major proportion of the total Indian production. Further, the petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and, is not related to any exporter or producer of the subject goods in the respective subject countries or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).
18. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the applicant satisfies the standing requirements for the subject goods and constitute domestic industry under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

CONFIDENTIALITY**Views of the Domestic Industry**

19. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to confidentiality:
- The responding exporter has resorted to excessive confidentiality in the questionnaire response file. Exporter questionnaire response filed by M/s Magotteaux Co Ltd needs to be rejected owing to the excessive confidentiality claimed by them. The exporter has claimed confidentiality on the information which the exporter is obliged to disclose publicly.
 - The exporter has abused the provisions of confidentiality, this has curtailed the right of domestic industry to defend their interest and such claims should not be accepted by the Authority.
 - Very basic information product name, grades, website information, channel of distribution, details of its offices has also been kept confidential, among others. No proper non confidential summary has been provided by the exporters.
 - Exporter has not given any information on factories involved in the production and the product produced, name of the documents, information regarding exports to India, sales of goods of the company, sales price structure, statement showing installed capacity, information related to cost of production, information related to subsidiary etc.
 - The exporter is required to give information with regard to surplus capacities with them, availability of alternate markets other than India, inventories of the article under investigation with the exporter, prices at which subject goods are being exported to third countries and local demand for the product, ascertain the price at which the subject exporters are likely to export the product and how the same compares with the domestic industry prices and non-injurious price. In the present case, the exporter had claimed confidentiality on all the information for above.
 - The exporter has not provided any non-confidential summary of the information filed by them and this has seriously curtailed the right of domestic industry to defend their interest and the exporter has abused the provisions of confidentiality. Such claims should not be accepted by the Authority and the exporters should be directed to disclose such information or provide sufficient non confidential summary of the information.
 - Even when a party has participated in the investigation but has not provided the available information sought by the Authority, the party could be treated as non-cooperative by the Authority.

Views of the other Interested Parties

20. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:
- M/s Magotteaux has sought confidentiality of the very same information which complainants themselves have sought confidentiality.
 - M/s Magotteaux has sought confidentiality of only that information which is business sensitive and revelation thereof to the competitor's may gravely harm business interest of Magotteaux.

Examination of the Authority

21. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

“Confidential information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule(2),(3)(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

22. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

MISCELLANEOUS ISSUES

Views of the Domestic Industry

23. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic Industry:
- i. The Brazilian Authority has initiated anti-dumping as well as anti-subsidy investigation against India for the same product. The anti-dumping duty imposed is 12.2% and CVD investigation is going on.
 - ii. The same is being done with an intention to curtail Indian Exports. Anti-dumping duty is imposed on Indian products despite export price being significantly higher than cost.
 - iii. The exporter has exported the goods under Chapter 84 instead of Chapter 73 to avoid anti-dumping duty. Attempt to evade Anti-dumping duty can be noticed from the practice of the exporter by exporting 186 MT of product under consideration under incorrect HS code.
 - iv. The domestic industry has already filed transaction wise import data which shows that in total 186 tonnes of import has been made imported under Chapter 84 along with relevant documents to establish that the product under consideration has been imported under the wrong classification.
 - v. It would be seen that since past two years, the exports of the product under consideration has significantly declined and the export price of the product under consideration has dramatically increased. The exporters of the subject countries have intentionally doctored the prices and quantities of their export to influence the sunset review investigation.
 - vi. An intentional action was taken by the exporters in order to influence the sunset review investigation and seek withdrawal of ADD.
 - vii. Besides the support from the parent companies, the Government of Thailand also provides protection to the company by keeping high customs duty on imports from India. Meanwhile, Govt. of India has given customs duty concession to the Thai producers.
 - viii. The FTA by India and Thailand provides special concessions to the producers/exporters in Thailand vis-a-vis other countries. While Govt. of India gave tariff concessions to Thailand for the product under consideration, the Thai Govt. did not reciprocate the grant of concessions to the Indian exporters.
 - ix. The intention behind ASEAN agreement was to encourage free trade between countries and to remove trade barriers and also to provide a good competitive market to the exporting countries. The exporters have taken undue advantage of the benefit offered to them under the ASEAN agreement.
 - x. With regard to considering 10% of customs duty for the product under consideration instead of NIL duty, the Hon'ble Supreme Court judgment of Haldor Topse may be referred and relied upon where the Hon'ble court confirmed the calculation of two differing dumping and injury margin for the same product owing to two different customs duties.

Views of the other Interested Parties

24. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
- i. The scope of review under Rule 23 of Anti- Dumping Rules is questioned, the DA is requested to look into a certain factors such as change in patterns of production, demand and requirement of the dumped product in the import countries since the imposition of duty, the change in prices in the exporting countries and in international market, to see whether the domestic industry is exploiting by raising the prices above international level.
 - ii. The Authorities is also required to address the factor s mentioned under Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement or else the determination of duty wouldn't be justifiable.

- iii. The basic custom duty the DA should take the basic custom duty of 10% while computing landing value of GM Balls from Thailand instead of the preferential rate of customs duty as enjoyed under the ASEAN Agreement.
- iv. The ASEAN Agreement does not envisage product by product reciprocal reduction of import duty. Such reciprocity is ensured at national level. Thus the argument that Thailand has not provided preferential rate of import duty on GM balls from India shouldn't be considered.
- v. The domestic industry has been granted excessive protection under the anti-dumping measures which lead to elimination of the competition.
- vi. The complainant is "virtually enjoying monopoly."
- vii. The Domestic Industry is exploiting the situation by raising the prices above the International level.

Examination of the Authority

- 25. With regard to the submission that customs duty should be considered at 10% as against 0% because the exporter enjoys the same under the ASEAN Agreement, the Authority notes that the law is very clear in this regard that the custom duty will be taken as it is.
- 26. The Authority notes that the law clearly envisages that the anti dumping duty can be extended further from time to time, if it is found that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty. Anti-dumping law is for removing unfair trade practice and providing a level playing field to the domestic industry. The Authority recommends anti-dumping duty only after following the requirements prescribed under the laws.
- 27. On the issue of monopolistic behaviour of the domestic industry, it is noted that the purpose of antidumping duty, in general, is to eliminate dumping which is causing or likely to (in case of SSR) cause injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in general interest of the country. From the antidumping rules, it is not borne out that a company, even if monopolistic, is prohibited from requesting to the Authority actions against the unfair imports.

NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

- 28. According to Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975 'Normal Value' in relation to an article means: -

"comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Views of the Domestic Industry

- 29. The Domestic Industry, inter alia, submitted as follows:
 - i. China needs to be treated as non-market economy for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status. This also implies that unless these conditions are not fulfilled/satisfied, the Chinese costs and prices cannot be adopted.
 - ii. Chinese producers are required to be treated as companies operating under nonmarket economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
 - iii. The only known imports from Thailand have not yet been reported in the customs data, and it appears that these consignments have been cleared in March, 2017. However, the petitioners are well aware of the volume and the price at which the Thai exporter has taken the order in the proposed POI and have adopted the same for the purpose of determination of normal value, export price and dumping margin.

Views of the interested parties

30. The other interested parties submitted as follows:

- i. Imports will certainly increase after duty is revoked but there is no parameter to show that the complainant will suffer.

Examination by the Authority**Normal Value in China**

31. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

32. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired in 11th Dec., 2016. Since the factum of dumping causing injury to the Domestic Industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is April 2016-March 2017. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
33. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as non-market economy countries in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

34. None of the exporter/producers have filed market economy questionnaire response. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proposes to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

All producers/exporters from China PR

35. As no producer of from China PR has co-operated in this investigation and provided any information for rebutting the non-market treatment as per para 8(2) of Annexure 1 of the AD Rules. Therefore, the presumption of non-market economy as per para 8(2) of Annexure 1 of the AD Rules remains un-rebutted. The Authority, therefore, has determined the Normal value in accordance with para 7 Annexure I of the AD Rules. In absence of sufficient information on record regarding the other methods as are enshrined in para 7 of Annexure I of the AD Rules, the Authority has determined the Normal value by adopting the method “any other reasonable basis”.
36. The Authority has therefore constructed the Normal value for China PR, for the purpose considering the best available information on record.

Normal value determination for M/s Magotteaux Co. Ltd, Exporter/producer from Thailand

37. It was first seen, whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporter/producer in their domestic market were representative and viable for permitting determination of Normal value on the basis of their domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents. The respondents have provided transaction-wise details of the sales of the like article in their home markets, the information so provided has been relied upon to determine the Normal value for the subject goods after carrying out the ordinary course of trade test and sufficiency test. The adjustments as claimed in respect of inland freight and credit costs and verified during the verification have been made to arrive at ex factory normal value.

Normal Value of all other exporters/producers from Thailand

The Authority notes that no other exporter/producer from Thailand has responded to the exporter' questionnaire. Therefore, the normal value in their cases has been determined on the basis of best facts available on record.

Determination of export price of China PR

38. None of the exporters from China PR have provided any information giving details of export price. Therefore, the Authority has determined the export price for producers/exporters of China PR on the basis of the DGCI&S transaction wise data. Accordingly, the weighted average net export price at ex-factory level, in respect of all exporters from China PR has been determined after making due adjustments for Ocean Freight, Marine Insurance, Port Expenses, Bank charges, Commission and Inland freight on the basis of best available information as mentioned in the Dumping Margin table.

Determination of Export Price of Thailand

Export price for the responding exporters M/s Magotteaux Co. Ltd., Thailand

39. The respondent has furnished information in Appendix 2 relating to exports to India. The adjustments have been claimed on account of inland freight, port handling charges, ocean freight and overseas insurance, as verified during the verification have been accepted for the determination of the net export price.

Determination of Export Price in respect of Non-Cooperative Exporters/Producers

40. Since no other response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from the subject countries; the Authority has determined the Export price as per ‘facts available’ in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The data has been collated as per the information available on record. Accordingly, the net export price in respect of the other producers/exporters from China PR and in respect of the producers/exporters from Thailand can be seen in the table below.

Determination of Dumping Margin

41. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from the respective subject countries have been determined as provided in the table below:

S.No.	Exporter/producer	Normal Value USD/MT	Export Price USD/MT	Dumping Margin USD/MT	Dumping Margin (%)	Range
1.	M/s Magotteaux Co. Ltd., Thailand	***	***	***	***	30-40
2.	All exporters/ producers from Thailand	***	***	***	***	30-40
3.	All exporters/ producers from China	***	***	***	***	0-10

Injury Determination

Views of Domestic Industry

42. The Domestic Industry has submitted as follows with regard to injury and causal link in case of all of the subject grinding media balls:
- The products continue to enter Indian markets at dumped prices; the withdrawal of the existing Anti-dumping measure shall lead to continued dumping and consequential injury to the domestic industry.
 - The domestic industry has not claimed injury in the present case and the fact that the domestic industry is earning profit in present has no relevance in case of SSR investigation as well as examination of likelihood.
 - The petitioners have already established that the exporter is exporting the product in India at dumped prices despite anti-dumping duty in existence. 44% EBDTA of AIA for the F.Y. 2015-16 (33% for 2016-17) as claimed by the exporter is baseless as it includes other non-operational income and margin on other NPUC products which is quite higher than G M Ball.
 - There are various kinds of castings and performance of other companies producing casting and comparing the same with the petitioners' performance is not relevant in this investigation.
 - It is contended that cessation of anti-dumping duty would lead to likelihood of dumping and injury and therefore duty should be continued is within the provisions as prescribed by law.
 - Performance of the domestic industry has improved over the present injury period after imposition of antidumping duty. In the event of cessation of existing dumping duty, domestic industry will be forced to reduce its prices to match the landed price of subject imports from subject countries.
 - In such an event, considering that the landed price of imports shall be below selling price and NIP of domestic industry, performance of the domestic industry shall deteriorate to a level where the domestic industry would be earning less than adequate profits.

Views of other Interested Parties

43. The following submissions were made by producers/exporters/importers/other interested parties with regard to injury to the domestic industry.
- The Domestic industry has been making superlative and abnormal profits.
 - The return on capital employed by AIA is beyond 22% which is the benchmark return.
 - The complainant are "well beyond recovery".
 - The export turnover of the AIA has increased consistently and thus, is in no need of protection.
 - Domestic industry is now globally competitive and there is no threat of material injury which likely exists.
 - Referring to the profits earned by domestic industry, it claimed that no material injury is being caused to the domestic Industry.

Examination by the Authority

44. The injury analysis made by the Authority here under addresses the various submissions made by the interested parties.
45. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of

such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

46. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
47. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
48. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.
49. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

(i) **Assessment of Demand/ Apparent Consumption**

50. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources.
51. The demand for the product under consideration is given below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Demand					
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend		100	96	103	106
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Trend		100	100	100	100
China	MT	***	***	***	***
Thailand	MT	***	***	***	***
Subject Countries as a whole	MT	***	***	***	***
Trend		100	550	299	241
Other Countries-Imports	MT	-	-	-	-
Total demand/consumption	MT	54,032	53,346	55,067	55,937

52. The Authority notes that the demand has shown increase over the injury period.

(ii) **Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry**

Import volume and Market Share

53. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

54. The table below summarizes the factual position with regard to import volumes and market share :-

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Imports - Volume					
Subject Countries as a whole	MT	***	***	***	***
Trend		100	550	299	241
Other Countries	MT	-	-	-	-
Total Imports	MT	***	***	***	***
Trend		100	550	299	241
Subject country Imports in relation to					
Consumption	%	0.19%	1.03%	0.54%	0.43%
Total imports	%	100%	100%	100%	100%
Indian production	%	0.06%	0.29%	0.17%	0.11%

55. On the basis of above, the Authority notes as follows:

- (a) The imports have increased since the base year.
(b) It is also noted that imports have remained low in relation to Indian demand and consumption.

(iii) Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

(a) Price Undercutting

56. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

57. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The price of the domestic industry was determined at the ex-factory level. The Authority has compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the subject goods.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Net Sales Realisation	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	105	96
CHINA (G12)					
Landed Price without ADD	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	100	99
Price undercutting	Rs/KG	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Price undercutting %	range	0-10	0-10	10-20	0-10
THAILAND					
Landed Price without ADD	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	109	92
Price undercutting	Rs/KG	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Price undercutting %	range	(0-10)	10-20	(0-10)	0-10

58. From the above, the Authority notes that the landed price of imports of subject goods from subject countries is below the net selling price of the domestic industry. The imports from subject countries are undercutting the selling prices of domestic industry.

(b) Price Suppression/ Depression

59. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Cost of sales	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	97	86
Net sales realization	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	105	96
Landed price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	102	90

60. The Authority notes that the import price from subject countries is lower than the selling price of the domestic industry in the injury period.

(iv) Economic Parameters relating to the Domestic Industry

61. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
62. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below:

(a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volume

63. Production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry moved as shown below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	132	142	173
Plant Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	107	134
Production-PUC	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	106	133
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	75	78

64. It is noted from above that the capacity, production and sales of the domestic industry have improved in absolute term as compared to base year. However, the capacity utilization of the plant has declined significantly.

(b) Market Share in Demand

65. The market share of the domestic industry moved as shown below:

Market Share in Demand	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Share of Domestic Industry	%	50.77%	49.29%	51.33%	52.19%
Share of other producers	%	49.04%	49.68%	48.12%	47.37%
Share of Imports of Subject Countries	%	0.19%	1.03%	0.54%	0.43%
Share of Imports of Other Countries	%	0%	0%	0%	0%
Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

66. It would be seen from the above that the market share of the domestic industry and other Indian producers have remained more or less similar throughout the injury period. Market share of the imports have remained in the same range.

(c) Profitability, return on investment and cash profits

67. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow is as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	745	813
Interest	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	55	85	67
Profit before Interest	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-219	685	811
Return on Capital Employed-NFA	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-232	471	541

68. It is noted that the profits, cash Profits and Return on capital employed of the domestic industry have improved throughout the injury period due to anti-dumping duty in existence.

(d) Inventories

69. Inventories with the domestic industry is as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	126	228
Inventory Per Day	MT/Days	10	11	13	23
Trend	Indexed	100	105	126	228

70. The inventory level of the domestic industry has consistently increased throughout the period. The inventory per day has also increased.

(e) Employment and Wages

71. Performance of the domestic industry with regard to employment, productivity and wages is as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	117	146
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	124	144
Productivity Per Employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	90	91
Productivity Per Day	MT/Days	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	106	133

72. On the basis of above, the Authority notes that the levels of employment and wages have increased throughout the injury period.

Magnitude of Dumping

73. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The analysis shows that the dumping margin determined against the subject country is positive.

Ability to raise Capital Investment

74. There is no verifiable information presented by the Domestic Industry and neither available on records that can imply that future investment in the sector can be marred by the presence of dumped imports from subject country.

Magnitude of Injury and injury margin

75. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

Table of Injury Margin

S.No	Exporter/producer	NIP USD/MT	Landed Value USD/MT	Injury Margin USD/MT	Injury Margin (%)	Range
1.	M/s Magotteaux Co Ltd, Thailand	***	***	***	***	0-10
2.	All exporters/ producers from Thailand	***	***	***	***	0-10
3.	All exporters/ producers from China	***	***	***	***	0 -10

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

76. The Authority observed that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if the anti-dumping duties were to be allowed to expire even if there is no current injury.

Submissions by the Domestic Industry

77. Following are the submissions made by the Domestic Industry with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury –

- i. Though the domestic industry's situation has stabilized after imposition of anti-dumping duty but looking at the surplus capacities in the subject countries, there is a clear likelihood of recurring of dumping and consequent injury to the domestic industry.

- ii. Cessation of anti-dumping duty in force is bound to result in intensified dumping of product from subject countries. Injury to the domestic industry is likely to recur in the event of cessation of anti-dumping duty.
- iii. There is a low volume of import due to ADD in force but the imports are at dumped price.
- iv. The exporter has sufficient freely disposable capacities and their capacities have been further expanded. As per public statements of the company they have the ability to produce 140,000 tons of grinding media balls per year.
- v. Demand for the subject goods in the subject countries is only 2900 MT per year. Earlier the capacity of the exporter was 80,000 MT per ton, which was already much beyond the demand of the subject goods in the subject countries. Further in last 2-3 year they have made further expansion and have declared their capacity as 140,000 MT per year.
- vi. The domestic industry has not claimed that the dumped imports have caused injury to the domestic industry. Various economic parameters have shown improvement under the protection umbrella of antidumping duty.
- vii. Production and sales of the domestic industry has improved, the same is due to the protection granted by the Designated Authority and establishes that injury earlier suffered by the domestic industry was due to dumping and the same got addressed with imposition of antidumping duty.
- viii. The profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have increased since the base year. The growth of the domestic industry improved with respect to various economic factors.
- ix. Dumping margin has been significant in the previous cases.
- x. The domestic industry's situation has improved because of antidumping duty being in force. Looking at the surplus capacities and limited demand of the subject goods in the subject countries, resumption of dumping and consequent injury to the domestic industry is not ruled out.
- xi. Availability of low priced imports from subject countries in the market would cause an adverse impact on the Domestic Industry as the Indian Market for the product under consideration is highly price sensitive.
- xii. The import from subject countries has drastically declined but future imports cannot be completely ruled out as is established by the current imports and offers given by them.
- xiii. The price undercutting without anti-dumping duty is positive, which clearly goes on to indicate that the dumped imports will undercut the domestic prices in case of cessation of existing anti-dumping duty.
- xiv. The issue to be examined is not whether there is current dumping or the domestic industry is suffering injury, but to examine, whether on the cessation of duties, if there is a likelihood of recurrence of dumping and injury.
- xv. The Authority need to examine, parameters such as whether there are sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports
- xvi. Absence of current dumping does not mean that, there is no likelihood of dumping in the event of cessation of anti-dumping duty. The absence of injury is entirely insufficient to conclude that the ADD need not be extended.
- xvii. Producers in subject countries have significant capacity indicating the future intensification of exports in the case of cessation of ADD.
- xviii. The dumping margin determined by the Petitioners is also positive and significant. In the event of cessation of Anti-dumping duty, the exporters will get a greater opportunity to dump the product under consideration into India, taking away the market share of the domestic industry.
- xix. Producers in subject countries maintain huge capacities to produce subject goods. M/s Magotteaux Co Ltd is world's largest producer of the product under consideration, has a market footprint of above 500,000 tons of grinding media and castings.
- xx. The price undercutting by the subject countries may force the Domestic Industry to reduce its prices further, resulting in the intensification of the exports to India in case of cessation of ADD, by the subject countries.
- xxi. The Indian market for the product under consideration is highly price sensitive; availability of such low priced imports from subject countries in the market would definitely cause an adverse impact over the Domestic Industry.
- xxii. Likelihood of future dumping can also be ascertained based on the fact that, exports from subject countries have drastically declined while the same is at a price significantly below normal value.
- xxiii. The factors relevant to likelihood of dumping are relevant to the likelihood of injury as well in the present case. Despite imposition of Dumping duties, imports have been made at dumped prices.

- xxiv. The dumping margin in the current POI is positive and significant with respect to China PR. As regards Thailand, there is dumping in low volume.
- xxv. Price undercutting without prevailing anti-dumping duties is positive.
- xxvi. Import prices are below selling price of the domestic industry, consumers will prefer the imported products resulting in the rise of imports.
- xxvii. The domestic industry shall have to reduce their selling price to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales; leading to severe price injury.
- xxviii. The Changed behavior of the exporters can be seen as a result of the imposition of the anti-dumping duties, exporting of products at dumped prices on the cessation of ADD is reasonably anticipated.
- xxix. The Designated Authority has in the past recommended extension of anti-dumping duties in similarly placed situations.
- xxx. There is no requirement for the Authority to examine or establish a causal link between dumping and injury. The only factor to be considered is the recurrence of the injury in case of cessation of ADD.

Views of the other Interested Parties

- 78. Following are the submissions made by the other interested parties with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury:
 - i. The Authority should also note that if they rely on dumping margins while determining the likelihood of continuation of duty; the same should be done under the ambits of Article 2.4. and injury determination should be based on “positive evidence” and an “objective examination”
 - ii. There is absence of positive evidence which can lead to reasonable conclusion that there is a chance of injury in the event anti-dumping duty is revoked..
 - iii. The complainant has failed to provide with cogent evidence in relation to establishing of likelihood of injury.
 - iv. The capacity of the domestic industry mainly M/s. AIA Engineering Ltd. has increased after the POI of the final investigation highlighting that the industry doesn't have any injurious effect and thus absence of likelihood of injury. The complainant has made capacity expansion in all three years.
 - v. The complainants have themselves confirmed that after expansion to a rated capacity of 4,40,000 MT, they would be the largest producer of grinding media globally, not just in India.
 - vi. The import of GM Balls from Thailand during the POI is 186 Mts which is less than 0.05% of the installed capacity of the complainant; laying down that such amount of import can never cause injury to the domestic industry.
 - vii. The Domestic industry has been making superlative and abnormal profits (Tables provided)
 - viii. Following facts have been laid wrongly in the petition:
 - a. Magotteaux Co. Ltd.; Thailand through its entities and associates is suppressing the cost of production. In this regard the exporter claimed that this is a false accusation and the complainant is trying to influence the Hon'ble Authority.
 - b. The facts regarding the installed capacity of Magotteaux and the domestic demand are wrong. Whole capacity installed is used to address demand of the Asia-Pacific market and not just India.

Examination of the Authority :

- 79. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules provides for the following:

(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation :

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Imports - Volume					
Subject Countries as a whole	MT	***	***	***	***
Other Countries	MT	-	-	-	-
Total Imports	MT	***	***	***	***
Total Imports	trend	100	550	299	241

80. The Authority notes that with the imposition of anti-dumping duty, the imports from subject countries have increased compared to base year. It is likely that in the event of cessation of anti-dumping duty, the volume of imports will further increase considering the unutilized capacities with the foreign producers.

b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports

81. This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of existing surplus capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. Domestic industry has claimed that the producers in subject countries are already faced with significant surplus capacities. Further, these producers have accepted that they are exporting the product to a large number of countries, currently a very small proportion is being exported to India which is being exported at a price below the prices in respect of India, thus showing likelihood of diversion of these exports to India in the event of withdrawal of Anti-Dumping duty. The domestic industry has furnished copies of a web articles showing recent expansion made by the exporters and information with regard to present demand in Thailand. The same has been taken on record.

82. On the basis of the questionnaire response filed by M/s Magotteaux Co. Ltd, Thailand and information made available by the Domestic Industry from the websites of the exporters as also the exporter questionnaire response filed by the exporter it can be seen that M/s Magotteaux have ample production capacities with them. They are also exporting Grinding media balls around the world. No other interested party has either controverted the information or provided any counter-factual information. Analysis of questionnaire response of the responding exporter shows that the exporter has not provided all relevant information in the form and manner prescribed with regard to transaction wise details of its exports to third countries, as prescribed in the questionnaire and therefore the Designated Authority has carried out analysis on the basis of available information. These capacities are in themselves more than the total demand and third country exports and can be considered as freely disposable capacities. The importance of such huge production capacities and exports by the producers/exporters cannot be ignored. The Thailand exporter has also expanded the capacities despite the fact that the existing capacities were much more than the total demand of the exporting country.

c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports

83. At the current landed price in India, there is positive price undercutting during POI without Anti-Dumping Duty in force. However, the imports do not have any suppressing or depressing effect on the domestic prices.

d) inventories of the article being investigated

84. As per the details given in the exporter questionnaire by the exporter from Thailand, the inventories have increased in POI as compared to base year as well as the previous year. It is noted that Inventories have been increasing despite the nature of the product, which is highly demand driven.

Causal Link

85. Under Section 9A (5), the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the product under consideration during the review investigation period or not. It was examined whether other parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It is noted as follows:

a) Volume and value of imports not sold at dumping prices:

86. Statement of imports from various countries shows that there are no imports of product under consideration from other countries. It cannot, therefore, be said that the imports from other countries have also caused injury to the domestic industry.

b) Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption:

87. The demand of the subject goods has increased over the injury period. The pattern of consumption with regard to grinding media balls has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry.

c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:

88. The Authority notes that there is no trade restrictive practice in grinding media balls which could have contributed to the injury to the domestic industry.

d) Developments in technology:

89. The Authority also notes that the technology for production of grinding media balls has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

e) Export performance:

90. Petitioners have exported the subject goods. However, they have not claimed injury in the domestic operations. Petitioners have provided costing and injury information for domestic sales separately. Hence, injury to domestic sales cannot be attributed to exports.

f) Performance of other products produced and sold by the domestic industry:

91. The performance of the domestic industry has improved over the period and has been attributed to the effect of anti-dumping duty.
92. The essential facts of the investigation, as gathered, analyzed and established by the Designated Authority during the course of the investigations on the basis of information received from various sources are hereby disclosed to the interested parties in order to enable them to offer their comments on these facts as stated by the Designated Authority.

Post Disclosure Comments

93. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below.

Views the Domestic Industry:

- i. Disclose communications sent to exporter and the replies filed by them post filing of initial questionnaire response. If there is anything confidential in the same, we request disclosure of NCV of the same.
- ii. Petitioner requests disclosure of [a] exporter verification reports (NCV), [b] communications exchanged with exporters (NCV), [c] the NCV version of information filed by the exporter post filing of initial questionnaire response.
- iii. The Authority has found that the domestic industry has not suffered injury in the present investigation. Such being the case, the present case is required to be decided on the basis of likelihood/threat examination. Such being the case, the likelihood analysis may not kindly be based on injury margin, as the purpose of injury margin is only to determine quantum of Anti dumping duty. It is also the practice of the Designated Authority wherein the Designated Authority has not modified the quantum of ADD when the Designated Authority found that the need for continuation/extension is based on likelihood of injury.
- iv. Since past two years, the exports of the product under consideration have significantly declined and the export price of the product under consideration has dramatically increased. This clearly shows that the exporters of the subject countries have intentionally doctored the prices and quantities of their export to seek withdrawal of antidumping duty and if the same does not work, influence the sunset review investigation.
- v. The imports entering in the Indian market at present is only 2% of the previous levels. Therefore, in case, the dumping margin and injury margin determined on the basis of these imports are highly unrepresentative of the likely behaviour of the exporter.
- vi. Producers have accepted that they are exporting the product to a large number of countries, currently a very small proportion is being exported to India which is being exported at a price below the prices in respect of India. This clearly shows that the producer is selling the product in other countries at a price lower than in India.
- vii. In the event of cessation of anti-dumping duty, the producer will divert its third countries exports to India since they will be able to fetch better prices in the Indian market and still be able to dump the product. As rightly pointed by the Authority that there is a likelihood of diversion of these exports to India in the event of withdrawal of Anti-Dumping duty.
- viii. Exporter has substantial production capacities. These capacities are in themselves more than the total demand and third country exports and can be considered as freely disposable capacities. This clearly shows that the capacities with the exporters not only more than the demand and exports to third countries. These excess capacities are likely to be utilized for exporting the product under consideration to India at dumped price in the event of cessation of anti-dumping duty and likely to cause injury to the domestic industry.
- ix. The Thailand exporter has also expanded the capacities despite the fact that the existing capacities were much more than the total demand of the exporting country. This clearly shows that despite having freely disposable capacities, the exporter is expanding its capacities, which clearly proves that in the event of cessation of anti-dumping duty, the exports to India is likely to increase at dumped prices causing injury to the domestic industry.

- x. Price undercutting is positive. This clearly shows that these imports despite anti-dumping duty in existence were at a price below the selling price of the domestic industry, as noted by the Authority at Para 82 of the disclosure statement.
- xi. Inventories with the exporters at Para 83 of the disclosure statement shows that the Authority has noted that the inventories of the exporter has increased throughout. This is despite the product being demand driven.
- xii. The increasing inventories with the exporters, freely disposable capacities and expansion plans of the exporters are their own admissions and show that the volume of dumped imports will increase and cause injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xiii. While the petitioner requests extension of existing antidumping duty, the petitioner submits that anti-dumping duty may be imposed as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed in US\$/kg.
- xiv. Determination of non injurious price is inappropriate;

Views of the other Interested Parties

- i. Authority must consider customs duty applicable to non-preferential rules of origin and not preferential duty under ASEAN Agreement. In the case of Phosphoric Acid from Korea, the Designated Authority ignored the preferential duty and adopted standard rate of duty.
- ii. It is submitted that the complainants as well as the exporter, both are exporting products in the same market (Asia Pacific, Africa and America). Both the complainants and the exporter has provided transaction wise data for export, and therefore, the Designated Authority have requisite information on the prevailing international prices. In view of the above, it is submitted that the Designated Authority must consider cost of production and international price to determine injury margin and not rely on the realized sales price of the complainants.
- iii. Several invoices have been submitted to show that the domestic industry is selling the product at a price below the landed value.
- iv. Appears that the DA has computed price undercutting of 0-10% on comparative analysis of landed price of import with the selling price of the domestic industry.
- v. Cash profit of the domestic industry has increased by 8 folds in the POI as compared to the base year. Profitability has increased by 40% whereas the profitability of casting industry is only 17-18%.
- vi. The Designated Authority has computed dumping margin, injury margin, price undercutting, price suppression/depression etc. on an aggregate basis. In this regard, it is submitted that there are differing grades of the PUC basis the chrome content and the size. Further, differing grades have varying cost of production, composition of raw materials as also end-users. It is submitted that parties have provided grade wise data. Accordingly, it is submitted that the comparison or determination of injury margin, dumping margin and the like should be on the basis of individual grades and not on an aggregate level. Aggregate level vitiates the entire sunset review proceedings.

Examination by Authority

- 94. Regarding, the impact of the agreement between India and Thailand, the Authority has evaluated the Landed Value as per the applicable custom duties. The Authority notes that on the one hand the preferential trade agreements provisions might lower the landed value, but at the same time the exporters could leverage this to increase their export realization by factoring the zero import duty advantage in export price as compared to other competitors which would though increase the landed value to some extent on the one hand and also decrease the dumping margin due to increase in export price. Therefore, these aspects may also warrant an adjustment. Therefore, the Authority has adopted its consistent practice of evaluating the landed value with applicable custom duties.
- 95. The Authority observes that the exporter has contended that the exports have been made at a price higher than the DI price and at the same time it has contended that the domestic industry has earned high profit and the profitability thereof, has improved. It is clarified that, the petitioner itself has not claimed that the imports are causing continued injury to the DI. The Authority observes that there exists a strong likelihood of continued dumping and consequently, the dumping of the product is likely to cause injury to the domestic industry. Since the present determination is based on threat to likelihood/ recurrence of dumping, the actual parameters relevant to actual injury are not substantially relevant.

96. Regarding the contention that the cost of production should be compared with international price to determine the injury margin and not rely on realized prices of the DI, the Authority has considered net sales realization and compared the same with landed price of imports. Further, the Authority has compared NIP with landed price of imports. The contention that the petitioner is also exporting at comparable prices to several countries is beyond the scope of the present likelihood of injury determination.
97. It is noted that the exporter has not sufficiently identified the product type involved either in domestic sales or exports to third countries. It is noted in this regard that cost and price of the product varies with a chrome content and size of the balls. The exporter however, has not identified size of the ball as a relevant consideration for identifying and segregating the imports. It is also noted that the exporter has not provided cost of production for all the grades which has been sold by the exporter in the domestic market or exported to third countries. It is thus noted that exporter has itself decided not to provide all relevant information to the Authority and has partially segregated the product into different types. Such being the situation, the only option with the Authority is to proceed on the basis of weighted averages.
98. Regarding, determination of grade-wise dumping and injury margin, it is noted that the responding exporter has not provided the requisite data for the same in the Exporter Questionnaire response. Neither, they have sought any clarification with the Authority with regard to the separate information that is required to be provided for different product types even during the oral hearing and have raised the issue only at the stage of post-disclosure comments. This is despite the fact that the questionnaire prescribed by the Authority clearly requires the exporters to provide separate information for different product types. Further, even during the table verification, such information was not provided readily and the same had to be called for through reminder. It is thus noted that exporter had made a conscious choice to not provide all relevant information to the Authority for grade wise determination. In the event of grossly inadequate exporter questionnaire response, the best available information has led the Authority to proceed on the basis of weighted averages.
99. As regards the contention that the volume of import is quite low in absolute terms or in relation to production and consumption, the Authority notes that in the present investigation petitioner itself has not claimed that imports are causing material injury. Nor has authority examined the case on the ground of continuation of injury. The present investigation has been conducted to determine whether dumping of the PUC is likely to cause injury to the domestic industry. Since the Authority is required to determine recurrence of injury in the present case, the actual volume of import in any case is not the sole relevant information for analysis of likelihood of injury. It is noted in this regard that the exporter has very significant exports of the product to a large number of countries as examined from the details of the questionnaire response filed by the exporter.

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

100. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

CONCLUSIONS

101. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of recurrence of dumping and consequent injury, the Authority concludes that:
- a) The subject goods are likely to enter the Indian market at dumped prices if the anti-dumping duties in force ceases to operate.
 - b) The situation of domestic industry is likely to deteriorate if the existing anti dumping duties are allowed to cease.
 - c) The deterioration in the performance of the domestic industry is likely to be because of dumped imports from the subject countries. Thus the anti-dumping duties are required to be extended.

RECOMMENDATIONS:

102. Having concluded that there is likelihood of recurrence of dumping and injury, if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended in respect of imports from subject countries.
103. Having examined the likelihood of dumping and injury to be imminent in case of expiry of the current measure in place, the Authority recommends continued imposition of Anti-Dumping Duty in place as recommended by the Authority vide Final Findings Notification No 14/34/2010-DGAD dated, 22nd May 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I and notified by the Central Government vide Notification No. 36/2012-Customs (ADD) dated the 16th July, 2012 for a period of five years.
104. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

SUNIL KUMAR , Additional Secretary & Designated Authority